शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

सीबीएसई : 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षा की नई तारीखें जारी कीं हैं। इनमें गणित, भूगोल और भौतिक विज्ञान शामिल हैं। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून को खत्म होंगी। पहले 12वीं की परीक्षा 14 जून को समाप्त होनी थी। सामान्य तौर पर लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती थीं और मार्च में समाप्त होती थीं, लेकिन इस बार कोविड के चलते यह आगे बढ़ गईं।

12वीं का शेड्यूल

विषय	पुराना	नया
फिजिक्स	13 मई	08 जून
मैथ्स	01 जून	31 मई
ज्योग्राफी	02 जून	03 जून

इसके अलावा पहले 13 और 14 मई को भी कुछ विषयों की परीक्षाएं होनी थीं। अब इन दोनों तारीखों में कोई परीक्षा नहीं होगी।

10वीं का शेड्यूल

विषय	पुराना	नया
साइंस	15 मई	21 मई
मैथ्स	21 मई	02 जून

फ्रेंच, जर्मन, अरबी, संस्कृत, रशियन, ऊर्दू और पंजाबी की तारीखें भी बदली गई हैं।

एमपी बोर्ड का बेतुका निर्णय: परीक्षा से पहले सिलेबस में दो-दो चैप्टर जोड़े, स्टूडेंट्स तनाव में

रामचंद्र पाण्डेय ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

कोरोना के चलते एमपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं में नवंबर में कम किए थे सिलेबस, गणित में दो, तो स्पेशल इंग्लिश में 3 चैप्टर जोड़े

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा से दो माह पहले फिर सिलेबस में बदलाव कर दिया है। मंडल ने इसी सत्र में नवंबर में कोरोना काल में प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए सिलेबस 30 प्रतिशत कम कर दिए थे। उस समय जो चैप्टर हटाए गए थे, उनमें से कुछ चैप्टर फिर से सिलेबस में शामिल कर प्रश्न-पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है। वह तनाव में हैं कि इतने कम समय में जोड़े गए विषय की तैयारी कैसे करेंगे। मंडल ने गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स और बॉयोलॉजी में नए चैप्टर जोड़े हैं। गणित में दो, जनरल इंग्लिश में दो और स्पेशल इंग्लिश में 3 चैप्टर जोड़े गए हैं।

12वीं के विषयों में बढ़े चैप्टर

- गणित : दो चैप्टर (वेक्टर मैथ एवं पीविमीय ज्यामिती)
- जनरल इंग्लिश : दो चैप्टर बढ़े
- स्पेशल इंग्लिश : तीन चैप्टर बढ़े
- हिन्दी : दो चैप्टर बढ़े

कोरोना काल में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, सीबीएसई सहित अन्य बोर्डों को सिलेबस 30 प्रतिशत कम करने के निर्देश दिए गए थे। सीबीएसई ने 30 प्रतिशत कोर्स कम करते हुए अलग-अलग चैप्टरों से कुछ टॉपिक कम किए थे। वहीं माशिमं के तत्कालीन चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने चैप्टर ही हटवा दिए थे। उसी के अनुसार स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की गई। उन्होंने उसी के अनुसार नया पैटर्न लाकर ब्ल्यू प्रिंट भी जारी किया था। अब जुलानिया के तबादले के बाद पीएस स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी के पास चेयरमैन का प्रभार है। उन्होंने फिर से सीबीएसई द्वारा कम किए गए कोर्स को मान्य कर ब्ल्यू प्रिंट जारी किया है। इसके चलते प्रत्येक विषय में दो-दो चैप्टर बढ़ गए हैं। इस तरह हर विषय में लगभग 25 से 30 प्रतिशत कोर्स बढ़ा है।

इनका कहना है

हमें अभी टीवर ने बताया कि वेक्टर गणित व ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें पांच एक्सरसाइज हैं। इसके लिए लगभग 30 फार्मूले हल करने होंगे। नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। डर लग रहा है कि नंबर कम न हो जाएं।
सुरेश कुमार, स्टूडेंट 12वीं, नवीन हायर सेकंडरी स्कूल, अरेरा कॉलोनी

नए ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार जनरल इंग्लिश में दो चैप्टर और स्पेशल में तीन चैप्टर बढ़ गए हैं। बच्चों को नए ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा।
-राजेश सिंह, अंग्रेजी टीचर

अभी हमारे पास शासन का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। जो नया ब्ल्यू प्रिंट आया है, उसमें जो सिलेबस पहले कम किया गया था, उसे जोड़ दिया गया है। शिक्षक अब उस कोर्स की तैयारी करा रहे हैं।
-पुष्पलता राव, प्राचार्य, कमला नेहरू स्कूल, टीटी नगर

सीधी बात : उमेश सिंह, सचिव, माशिमं

- परीक्षा के ऐन पहले नए चैप्टर बढ़ाना क्या सही है। इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा?
- बच्चों के लिए कोर्स में जो बहुत जरूरी है, उसे ही शामिल किया गया है। सभी विषयों में चैप्टर नहीं बढ़े हैं। टीवर्स को भी अतिरिक्त जोड़े गए कोर्स से प्रश्न व अंकों का रेशियो कम करने को कहा गया है।
- एमपी बोर्ड के सिलेबस में बार-बार बदलाव क्यों किया जा रहा है, जबकि सीबीएसई ने एक बार में ही सिलेबस कम कर दिए थे?
- प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार सीबीएसई के कोर्स में कटौती की गई थी, इसलिए उसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोबारा बदलाव करने की जरूरत पड़ी है।
- जिस कोर्स को बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, उसे जोड़ने से बच्चों का रिजल्ट खराब नहीं होगा?
- अधिक कोर्स नहीं बढ़ा है। अभी दो माह हैं, बच्चों की तैयारी करा दी जाएगी। उनका रिजल्ट खराब नहीं होने दिया जाएगा।

कोरोना के चलते माशिमं ने नवंबर में कम किया था 10वीं-12वीं का सिलेबस

एमपी बोर्ड का बेतुका निर्णय: परीक्षा से पहले सिलेबस में बढ़ाए चैप्टर, तनाव में स्टूडेंट्स

रामचन्द्र पाण्डेय • भोपाल
मो.नं. 9893231237

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा से दो माह पहले बेतुका निर्णय लेते हुए फिर 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। मंडल ने इसी सत्र में नवंबर में कोरोना काल में प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए सिलेबस 30 प्रतिशत कम कर दिए थे। उस समय जो चैप्टर हटाए गए थे, उनमें से कुछ चैप्टर फिर से सिलेबस में शामिल कर प्रश्न-पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है।

पीपुल्स समाचार
मुद्दत

स्टूडेंट्स और पैरेंट्स तनाव में हैं कि इतने कम समय में जोड़े गए विषय की तैयारी कैसे हो पाएगी। जानकारी के अनुसार, मंडल ने 12वीं में गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स और बॉयोलॉजी में नए चैप्टर जोड़े हैं। गणित में दो, जनरल इंग्लिश में दो और स्पेशल इंग्लिश में 3 चैप्टर जोड़े गए हैं। इसी तरह 10वीं में भी कुछ चैप्टर जोड़े गए हैं। दरअसल, कोरोना काल में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, सीबीएसई सहित अन्य बोर्डों को सिलेबस 30 प्रतिशत कम करने के निर्देश दिए गए थे। सीबीएसई ने 30 प्रतिशत कोर्स कम करते हुए अलग-अलग चैप्टरों से कुछ टॉपिक कम किए थे। वहीं माशिमं के तत्कालीन चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने चैप्टर ही हटवा दिए थे। उसी के अनुसार स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई भी कराई गई और उसी के अनुसार नया पैटर्न लाकर ब्ल्यू प्रिंट भी जारी किया गया था। जुलानिया के तबादले के बाद पीएस स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी के पास चेयरमैन का प्रभार है। उन्होंने फिर से सीबीएसई द्वारा कम किए गए कोर्स को मान्य कर ब्ल्यू प्रिंट जारी कराया है। इसके चलते प्रत्येक विषय में दो-दो चैप्टर बढ़ गए हैं। इस तरह हर विषय में लगभग 25 से 30 प्रतिशत कोर्स बढ़ गया है।

सीधी बात — उमेश सिंह, सचिव, माशिमं

- **परीक्षा के ऐन पहले नए चैप्टर बढ़ाना क्या सही है। इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा?**
  -बच्चों के लिए कोर्स में जो बहुत जरूरी है, उसे ही शामिल किया गया है। सभी विषयों में चैप्टर नहीं बढ़ाए गए हैं। टीचर्स को भी अतिरिक्त जोड़े गए कोर्स से प्रश्न और अंकों का रेशियो कम करने को कहा गया है।
- **सिलेबस में बार-बार बदलाव क्यों किया जा रहा है, सीबीएसई ने एक बार में ही सिलेबस कम कर दिए थे?**
  -प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार, सीबीएसई के कोर्स में कटौती की गई थी, इसलिए उसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोबारा बदलाव करने की जरूरत पड़ी है।
- **जो कोर्स बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, उसे जोड़ने से रिजल्ट खराब नहीं होगा?**
- कोर्स ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। अभी परीक्षा में दो माह बचे हैं, बच्चों की तैयारी करा दी जाएगी। उनका रिजल्ट खराब नहीं होने दिया जाएगा।

12वीं के इन विषयों में बढ़े चैप्टर

- गणित: दो चैप्टर (वेक्टर मैथ एवं ट्रिग्नोमेट्री)
- जनरल इंग्लिश: दो चैप्टर बढ़ाए
- स्पेशल इंग्लिश: तीन चैप्टर बढ़ाए
- हिन्दी: दो चैप्टर बढ़ाए गए है

रिजल्ट पर पड़ेगा असर

नए ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार जनरल इंग्लिश में दो चैप्टर और स्पेशल इंग्लिश में तीन चैप्टर बढ़ गए हैं। बच्चों को नए ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। इससे रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा।
राजेश सिंह, अंग्रेजी टीचर

अभी हमारे पास शासन का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। हां, जो नया ब्ल्यू प्रिंट आया है, उसमें जो सिलेबस पहले कम किया गया था, उसे जोड़ दिया गया है। शिक्षक उस कोर्स की तैयारी करा रहे हैं।
पुष्पलता राव, प्राचार्य, कमला नेहरू स्कूल, टीटी नगर

हमें मैथ्स के टीचर ने अभी बताया है कि वेक्टर गणित और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें पांच एक्सरसाइज हैं। इसके लिए लगभग 30 फार्मूले हल करने होंगे। अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। डर लग रहा है कि कहीं नंबर कम न हो जाएं।
सुरेश कुमार, स्टूडेंट 12वीं, नवीन हायर सेकंडरी स्कूल, अरेरा कॉलोनी

पुत्री को अतिथि शिक्षक बनाने पात्र को बनाया अपात्र

मामला कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर का

सतना ■ राज न्यूज नेटवर्क

सतना जिले के रामनगर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी पद के वर्ग 1 के अंतर्गत रिक्त अतिथि शिक्षक के पद पर विगत वर्षों से कार्यरत रुचि मिश्रा को इस वर्ष प्रभारी प्राचार्य ने अपात्र घोषित करके अपनी पुत्री को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी है जबकि इस संबंध में शिकायती आवेदन देते हुए पूवज़ से कार्यरत अतिथि शिक्षक वर्ग 1 रुचि मिश्रा ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी की सूची एवं स्कोर कार्ड में उनका नाम सबसे ऊपर है और योग्यता के आधार पर उनका ही चयन होना चाहिए परंतु प्राचार्य महोदय द्वारा अपनी पुत्री को अतिथि शिक्षक पद पर नियुक्त करने हेतु सारे नियम कानूनों को दरकिनार कर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया एवं जबरन अपनी पुत्री को उक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया है इस संबंध में रुचि मिश्रा द्वारा लगातार संबंधित अधिकारियों से उचित कार्यवाही की गुहार लगाई जा रही है।

शासन के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे प्रभारी : उपरोक्त संबंध में आवेदक रुचि मिश्रा द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग को दिए गए आवेदन में कायज़ाही करते हुए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सतना को संबंधित प्रकरण का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निदेज़शित किया गया जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा सहायक संचालक के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिनांक 1 फरवरी को संबंधित प्रकरण की जांच कराई गई जिसमें जांच टीम के प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि कुमारी %योति त्रिपाठी जो कि प्रभारी प्राचार्य की बेटी है कि अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में अंग्रेजी पद पर नियुक्ति शासन के आदेश के विरुद्ध है जो न्याय संगत नहीं है और प्रभारी प्राचार्य बृजेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के 1,2,3 के विपरीत होकर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

आवश्यक कार्रवाई की मांग

इस संबंध में आवेदक रुचि मिश्रा द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय की ओर आवेदन भेज कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है बहराल देखना यह होगा कि क्या वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने वाले उक्त प्राचार्य को शासन प्रशासन कब तक दंडित करता है और नियुक्ति पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे रुचि मिश्रा को शिक्षा विभाग द्वारा न्याय मिल पाता है या फिर उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा।

युवक कांग्रेस ने बाल आयोग से की शिकायत

स्कूलों में लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप

चैलेंज, भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूल खुलने के बाद फीस वसूले जाने की शिकायतें आ रही हैं। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए युवक कांग्रेस मैदान में उतर आया है। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली पर अंकुश लगनी चाहिए। अभिभावकों से लेट फीस के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। इधर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलते ही संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। युवक कांग्रेस मध्यप्रदेश मीडिया के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि फीस वसूली समेत अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से शिकायत दर्ज कराई। उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इसमें जबरन वसूली की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हमने उन्हें बताया कि प्रदेश के ऐसे स्कूलों पर नकेल कसना है। सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल लेट फीस के नाम पर मनमानी कर रहे हैं।

'फर्जी हस्ताक्षर कर शिक्षिका ने वेतन निकाला'

श्योपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। लुहाड़ गांव के ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी वकील सिंह रावत को आवेदन सौंपा। इसमें सरकारी माध्यमिक विद्यालय लुहाड़ में पदस्थ शिक्षिका द्वारा स्टाफ रजिस्टर पर फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन निकालने की शिकायत की है।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी मिडिल स्कूल लुहाड़ में पदस्थ शिक्षिका वंदना गौतम 2 फरवरी को छुट्टी का आवेदन देकर अपने पति का इलाज कराने दिल्ली चली गई थी, लेकिन स्टाफ रजिस्टर पर नियमित रूप से हस्ताक्षर हो रहे हैं। जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी उतनवाड़ ने फर्जी मेडिकल आवेदन जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी स्वीकृत करके शाला में रख लिया। स्टाफ

शिकायत

- **ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन सौंपकर की शिकायत**
- **ग्रामीण बोले - इस मामले की जांच कराई जाए**

रजिस्टर में कॉलम खाली छोड़ दिया, फरवरी में पूरे महीने अनुपस्थित रहने के बाद जब शिक्षिका स्कूल पहुंची तो रजिस्टर पर हस्ताक्षर करा लिए और छुट्टी आवेदन को फाड़कर फेंक दिया। स्टाफ रजिस्टर में सिर्फ 2 से 4 फरवरी तक की सीएल चढ़ाई गई है। इसके बाद शिक्षिका 5 फरवरी को जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी को छुट्टी का आवेदन देकर गई थीं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, वह स्कूल नहीं आ सकती हैं। जब मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उपस्थिति के साथ सिक्नेस फिटनेस जमा कर दूंगी। शिक्षिका के आवेदन के अनुसार रजिस्टर में 5 व 6 फरवरी की सीएल दर्शाई गई है, जबकि 5 फरवरी से 13 तक शिक्षिका विद्यालय से अनुपस्थित रही। स्कूल में उपस्थित होने के बाद शिक्षिका ने हस्ताक्षर कर दिए। जब तक शिक्षिका विद्यालय नहीं लौटी, तब तक स्टाफ रजिस्टर के कॉलम को खाली रखा गया। इसलिए इसकी जांच कराई जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिकायत करने वालों में रामकरण मीणा, कमल किशोर मीणा, रामलखन, राधेश्याम, गजेन्द्र सिंह, सुरेश मीणा आदि के नाम शामिल हैं।

स्कूलों में फीस प्रतिपूर्ति में अनियमितता जांच में खुली पोल, जिला प्रोग्रामर दोषी

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के निजी स्कूलों को आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति के रूप में अनियमित भुगतान हुए। इस आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी ने भी माना कि नियमविरुद्ध तरीके से राशि का भुगतान किया गया। अशासकीय विद्यालयों की जांच का प्रस्ताव आर्थिक अनियमितता किए जाने के आरोप सिद्ध होने के बाद 640 अशासकीय विद्यालयों की गहन जांच के लिए विभाग को लिखा गया है।

जांच कमेटी ने जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्रोग्रामर पारस राय को इसमें दोषी माना है। जांच कमेटी ने जांच में पाया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों को जारी फीस प्रतिपूर्ति में वित्तीय अनियमितता बरती गई है। इससे शासन को भी अर्थिक क्षति का नुकसान

हुआ है। इसमें 67 लाख 10 हजार की वसूली के लिए एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच के दौरान पाया गया जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने वेदांत पब्लिक स्कूल भेड़ाघाट को 53 लाख 9 हजार 640 रुपए फीस प्रतिपूर्ति में फर्जी तौर पर बच्चों के नाम दर्ज कर वित्तीय अनियमितता की गई है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर भी शामिल है। उक्त आशय के आरोपों को प्रारंभिक जांच में सही माना गया है।

जिपं सदस्य ने लगाए थे आरोप: जिला पंचायत सदस्य विजय क्रांति पटेल एवं उन्नति मेश्राम द्वारा जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर निजी स्कूलों को फर्जी तरीके से फीस प्रतिपूर्ति की राशि आवंटित किए जाने की शिकायत मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह से की गई थी।

काम किया नहीं, वेतन लिया

जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि अधिकृत कर्मचारियों का वेतन आहरित न करते हुए अनाधिकृत कर्मचारियों का वेतन आहरित किया गया है। यहां तक कि कई कर्मचारियों को बिना काम के वेतन दिया गया।

सेवा पुस्तिका अनुमोदन न कराने वाले प्राचार्यों पर हो कार्रवाई

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अध्यापकों की सेवा पुस्तिका में अनुमोदन नहीं करने वाले प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक मुकेश सिंह ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं की अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों कि सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापक संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में सम्मिलित प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन कोष एवं लेखा से कराया जाना है। इसके वावजूद जिले के प्राचार्यों की उदासीनता के कारण अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कोष एवं लेखा को ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा रही है। जिससे कोष एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा संवंधित सेवा पुस्तिका का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, जिससे अध्यापकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा स्पष्ट आदेश कर सभी प्राचार्यों एवं आहरण संवितरण अधिकारियों से जल्द सेवा पुस्तिका के अनुमोदन का पत्र भी जारी कर चुके हैं उसके वाद भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है।

संघ के मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, प्रणव साहू, नितिन अग्रवाल, तरुण पंचोली, राकेश दुवे, मनीष लोहिया, विष्णु पांडे, आनंद रैकवार, श्याम नारायण तिवारी, मनोज सेन, मो. तारीक, धीरेंद्र सोनी, गणेश उपाध्याय, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, राकेश पांडे, विजय कोष्टी, मनीष शुक्ला, सुदेश पांडे, संतोष तिवारी, सतीश पटेल आदि ने कलेक्टर जवलपुर से मांग की है कि सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन ना कराने वाले प्राचार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

स्कूल खुल गए, लेकिन डर ऐसा कि आनलाइन ही कर रहे पढ़ाई

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूलों में कक्षाएं तो लग रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम बनी हुई है। ज्यादातर विद्यार्थी सुरक्षित तरीके से घर में रहकर ही पढ़ाई करने पर जोर दे रहे हैं। वे आनलाइन कक्षाओं का ही लाभ उठा रहे हैं। शुरू में जहां 10 फीसद ही विद्यार्थी स्कूल पहुंच रहे थे। अब उनकी मौजूदगी 70 फीसद तक हो गई है, लेकिन 30 फीसद अभी तक घर में आनलाइन के सहारे कोर्स पूरा करने में जुटे है। छात्र कोरोना संक्रमण और सुरक्षा कारणों के चलते स्कूलों से दूरी बनाए हुए हैं। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति भी लेनी जरूरी है ऐसे में शिक्षक भी परेशान हैं। इन दिनों शहर के अधिकांश स्कूलों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।

एक से पांच तक स्कूल नहीं खुलेंगे: शासन ने भी साफ कर दिया है कि कक्षा एक से पांचवी तक स्कूल नहीं खुलेंगे। यहां आनलाइन ही पढ़ाई होगी। ऐसे में स्कूल पहले ही आनलाइन पढ़ाई पूरी करवा चुके हैं। अब ऐसे स्कूल आनलाइन ही परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गए हैं। ज्यादातर स्कूलों ने पांचवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का कार्यक्रम तक जारी कर दिया है। मार्च तक अधिकांश स्कूलों में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या सामने आ रही है तो वहीं बच्चों के पास मोबाइल न होना भी परेशानी की वजह बन रहा है। जिले के 2250 से अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं।

दोहरी पढ़ाई को मजबूर शिक्षक

छात्रों की आधी मौजूदगी के कारण कक्षाओं में शिक्षकों को दोहरी पढ़ाई करवानी पड़ रही है। पहले आफलाइन क्लास होती थीं है अब आफलाइन के अलावा आनलाइन भी कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं। दोहरी जवाबदारी से शिक्षक परेशान हैं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं ऐसे में उनके सामने परिणाम सुधारने की भी चुनौती बनी है।

कोविड-19 को देखते हुए फिलहाल प्राइमरी और मिडिल में कक्षाएं आनलाइन ही लगाई जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पढाने के लिए निर्देश दिए गए है।

-डॉ. आरपी चतुर्वेदी, डीपीसी

शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास होना चाहिएः मुख्यमंत्री

शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

शिक्षा का अर्थ तोते की तरह रटना, बस्ते के बोझ से दबे रहना और परीक्षा देना नहीं है। शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास तथा उनकी प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में 21वीं सदी में शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कही। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद् राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए हैं।

शिक्षा पथ प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष रविंद्र कान्हरे, आयोजन समिति के संयोजक डॉ शशि रंजन अकेला आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा पथ प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन भी किया।

मप्र पहला राज्य, जहां नई शिक्षा नीति को लागू करने गठित हुआ टास्क फोर्स

कार्यक्रम में शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि कोई संस्थान अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। शिक्षा में सुधार के लिए टास्क फोर्स बनेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षाविदों को जोड़ा जाए, जो नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को मध्यप्रदेश में किस तरह व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, इस संबंध में सुझाव दें।

इन विषयों पर होगा मंथन

इस दो दिवसीय संगोष्ठी में नई दिल्ली, हैदराबाद, मेरठ, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, बिहार और बिलासपुर समेत अन्य जगहों से कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविद् शामिल होंगे। ये सभी विषय विशेषज्ञ अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षक और शिक्षा के प्रावधान, नेतृत्व, शासन और शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का विनियमन, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता और मानक विषय, छात्रों के अधिकार एवं विशेष शिक्षा, अंग्रेजी भाषा अध्ययन, शिक्षा में प्रयोग, शिक्षक-शिक्षण संस्थाओं की बहुसंकायी प्रकृति जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सिफारिशों को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

मंथन से उपजे विचार मील का पत्थर साबित होंगे

श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सतत प्रयास कर रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित गुणवतापूर्ण और ज्ञान आधारित होना चाहिए। इस मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा।

आत्म-निर्भर मप्र में शिक्षा का अहम स्थान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाए गए रोड मैप में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में उच्च गुणवतायुक्त सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। अच्छी तकनीकी शिक्षा के लिए ग्लोबल स्किल पार्क तथा आदर्श आईटीआई बनाए जा रहे हैं।

31 मार्च तक आवासीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे

मुरैना । जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी अन्तर्गत विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कक्षा 6 वीं आवेदन के लिये प्रारंभ तिथि 08 मार्च 2021 से अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 रहेंगी। सीट संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2021-22, अप्रैल 2021 से प्रारंभ, कक्षा 6 वीं एवं 9 वीं में प्रवेश 8 मार्च 2021 से होगा। अंतिम तिथि 31 मार्च 2021, सायं 5 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे।

भास्कर

परेशानी • मुरार के नवयुग जूनियर स्कूल के 10 छात्रों से कलेक्टर से जनसुनवाई में की शिकायत

ट्यूशन फीस के नाम पर कुछ स्कूल कर रहे मनमानी, कलेक्टर तक पहुंचीं शिकायतें

सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर

पिछले साल सालाना फीस 13 से 15 हजार रुपए थी, कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश के बाद भी सालाना फीस इतनी ही है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दे कि वे अलग-अलग कक्षाओं की ट्यूशन फीस का खुलासा करें ताकि पालक व छात्रों को राहत मिल सके। इस तरह की शिकायत मुरार के नवयुग जूनियर स्कूल के 10 छात्रों से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से 2 मार्च को जनसुनवाई में की। इसके बाद जांच का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है।

6 किश्तों में फीस देने की छूट आज से प्रभावी

- फीस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने 1 मार्च को स्पष्ट किया है कि स्कूल पालकों से 2019-20 और 2020-21 की फीस ले सकेंगे। यह छह समान किश्तों में वसूल होगी। इसकी शुरुआत 5 मार्च से होगा और अंत 5 अगस्त 2021 को।
- उक्त फीस न देने किसी भी छात्र को भौतिक या फिर ऑनलाइन क्लास से नहीं रोका जा सकेगा। स्कूल किसी छात्र का परीक्षा परिणाम भी नहीं रोक सकेंगे। पालक को यदि भुगतान में दिक्कत है तो वह आवेदन स्कूल को देगा। स्कूल ऐसे आवेदनों का निराकरण करेंगे।
- फीस वसूली संबंधी उक्त निर्देश शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए मान्य नहीं होंगे। बकाया होने पर भी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के पालकों से अंडर टेकिंग लेकर उन्हें परीक्षा में शामिल

40% पालकों ने जमा नहीं की ट्यूशन फीस

करीब 40 फीसदी पालकों ने अभी तक कोरोना संक्रमण काल की फीस जमा नहीं की है। स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश है। इस हिसाब से पालकों को गत वर्ष की तुलना में 15 से 20% का फायदा होगा। किसी स्कूल की शिकायत है तो डीईओ जांच कर सकते हैं।

-राहुल श्रीवास्तव, ग्वालियर सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसो.

फीस की मनमानी की शिकायत मिली है

फीस को लेकर मनमानी की चार शिकायतें मिली थीं। स्कूलों से जानकारी मांगी गई और उन्हें निर्देश दिए गए कि वे कोरोनाकाल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलें। कुछ शिकायतें फीस माफ कराने को लेकर मिली हैं पर नियमों में यह संभव नहीं है। कोई पालक या छात्र ट्यूशन फीस को लेकर शिकायत करेगा तो उसकी जांच होगी।

-विकास जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 65 प्रतिशत से कम ना हो : सिंह

मण्डला ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने दसवी एवं बारहवी बोर्ड की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में जिले का बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम बेहतर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 65 प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कक्षा नवमीं से बाहरवी तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों को नोट्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्कूलवार उपस्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संकुल प्राचार्यो एवं बीईओ से स्कूलों में दर्ज संख्या में कमी के कारण पूछें। उन्होंने दर्ज संख्या को बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सर्वाधिक ड्रापआऊट स्कूलों तथा कक्षाओं की जानकारी ली। सिंह ने कहा कि शिक्षक अभिभावकों से बात करें। उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता होने पर घर-घर जाकर पालकों एवं बच्चों से उनकी समस्याएं जानें।

स्कूल नियमित भेजने करें अपील

उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने एवं परीक्षाओं में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ऐसी व्यवस्था करे कि बोर्ड परीक्षाओं में सभी बच्चे अनिवार्यतः परीक्षा में बैठें, परीक्षा में अनुपस्थित न रहें। उन्होंने स्कूलों में आयोजित की गई अर्द्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करते हुए असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की जानकारी ली एवं संबंधितों से कारण जाने। सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा वहां के शिक्षकों का बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर परिणाम आने तक वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

असंतोषजनक परिणाम वाले को नोटिस जारी के निर्देश

इसी प्रकार उन्होंने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में असंतोषजनक परिणाम वाले संबंधित संकुल प्राचार्यों और बीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संकुल प्राचार्यों को बोर्ड परीक्षाओं तक उनके स्कूलों में व्यवस्थाओं को सुधारने जरूरी अधिकार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं तक संकुल प्राचार्य आवश्यकता होने पर अन्य स्कूलों के शिक्षकों का दूसरे स्कूलों में अटैचमेंट करा सकते हैं ताकि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा होने तथा अन्य तैयारियों में सहयोग मिल सके। सिंह ने कहा कि लापरवाह अतिथि शिक्षकों को तत्काल हटाएं। सिंह ने बच्चों को नोट्स उपलब्ध कराते हुए उनका नियमित रूप से रिविजन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक स्तर पर टेस्ट भी लिया जाए। उन्होंने जिले के पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। बोर्ड परीक्षाओं के तैयारियों में स्कूल विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करें।

कम प्रगति दिखाने वाले शिक्षकों की रोकी जाएगी वेतन

कलेक्टर ने कहा कि मॉडल स्कूल तथा उत्कृष्ट विद्यालय के परीक्षा परिणाम 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 40 प्रतिशत से कम प्रगति दिखाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की वेतन रोकी जाएगी। उन्होंने मुनू मोहगांव के शिक्षकों के वेतन रोकने के निर्देश दिए तथा प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सिंह ने कहा कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों को उत्तीर्ण करने के लिए शिक्षक विशेष प्रयास करें। उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं देते हुए उनकी मदद करें। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्रों तक पहुचने तथा नियमित रूप से स्कूल आने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को बेहतर करने के लिए आगामी दिनों में संकुल प्राचार्यो, बीईओ, बीआरसी एवं शिक्षकों को भरपूर मेहनत करना होगा। शिक्षक अभिभावकों से मिलें, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं लें तथा प्रतिदिन 2-2 स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले, सहायक संचालक मसराम, एपीसी मुकेश पांडे तथा संबंधित उपस्थित थे।

निजी स्कूल संचालकों की नहीं चलेगी मनमानी, जबरन फीस वसूली तो होगी कड़ी कार्रवाई

स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए

सीधी ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देकर बताया है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के सम्बन्ध में तथा पालकों से जबरन फीस की वसूली सम्बन्धी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए निर्देश प्रसारित किया गया है।

किस्तों में ले सकेंगे फीस

उन्होने बताया कि निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए तथा इसके साथ-साथ शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभागीय परिपत्रों द्वारा नियत की गई फीस छात्रों/अभिभावकों से एकत्र कर सकेंगे । उक्त फीस छह समान किस्तों में ली जा सकेगी जो 05.03.2021 से प्रारंभ की जाकर 05.08.2021 को समाप्त होगी। निजी विद्यालय प्रबंधन ऊपर दिये अनुसार बकाया एरियर्स/लम्बित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास अथवा विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे।

परीक्षा परिणाम नहीं रोकेंगे

इस आधार पर उक्त विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा। भुगतान आदेश के सन्दर्भ में यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो रही है तो ऐसे अभिभावकों को यह छूट होगी कि वे अपनी कठिनाई के सम्बन्ध में अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन सम्बन्धित स्कूल को प्रस्तुत कर सकेगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त अभ्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक विचारण में लिया जाकर प्रकरणवार निराकरण किया जाएगा। व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा यथा सूचित एवं नियत की गई फीस को अभिभावकों द्वारा देय समय अनुसार भुगतान किया जाना होगा। अभिभावकों/छात्रों द्वारा शुल्क भुगतान न करने के आधार पर अथवा बकाया होने के आधार पर वर्ष 2021 की आगामी कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने हेतु किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित अभिभावक/छात्र से अण्डरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाए।

इन लागू होंगे निर्देश

उक्त निर्देश समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मप्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति अथवा पालकों से जबरन फीस की वसूली इत्यादि सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

सागौर हायर सेकंडरी स्कूल दसवीं की 80 छात्राओं को दिए टैबलेट

इंदौर • डीबी स्टार

अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगी छात्राएं

शासकीय कन्या हायर सेकंडरी स्कूल ग्राम सागौर कुटी में 10वीं की 80 बालिकाओं को 20 लाख रुपए की लागत के डिजिटल टैब बांटे गए। स्कूल के प्रधान पाठक बालकृष्ण शुक्ला ने बताया कि छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए निजी कंपनी ने टैब भेंट किए हैं, ताकि वह कोरोना के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। कंपनी के प्रतीक सेठे ने बताया कि टैबलेट में कक्षा 3 से 10 तक का माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के वीडियो लेसन हैं। इसके जरिए विद्यार्थी जरूरत के अनुसार आसानी से सीख सकते हैं। इस अवसर प्राचार्य अरुणा शर्मा, शैलेंद्र पंवार, रतनलाल टटवाड़े, कमलेश पाठक राजेंद्रपाल सिंह डंग, अजय पाठक आदि मौजूद थे।

लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बाद बंद हुई शैक्षणिक गतिविधियां अब धीरे-धीरे फिर शुरू हो रही हैं। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें शैक्षणिक के साथ ही गैर शैक्षणिक गतिविधियां भी शामिल हैं। इन गतिविधियों को गति देने के लिए शासन-प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में नुकसान न उठाना पड़े। इसी क्रम में शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्र सागौर कुटी और मांगलिया में कार्यक्रम आयोजित किए। सागौर में जहां छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए टैबलेट दिए गए, वहीं मांगलिया में विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने के लिए साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें विभिन्न मॉडल का प्रदर्शन किया गया।।

साइंस एग्जीबिशन में छात्रों ने मॉडल बनाकर दिखाया हुनर

इंदौर। श्री महादेव साहरा सुकृत ट्रस्ट और संस्था आस ने विज्ञान दिवस पर एग्जिबिशन का आयोजन किया। इसमें मांगलिया क्षेत्र के 50 बच्चों ने भाग लिया। छात्र सचिन ने विंड मिल बनाकर प्रथम, सोनू यादव ने वाटर कूलर बनाकर द्वितीय तथा श्रीकांत ठाकुर ने प्रिंटर मशीन बनाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर जितेंद्र परमार और वसीम इकबाल ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे। कार्यक्रम में नरेंद्र चौहान, गोविंदा ठाकुर और रागिनी परिहार की सक्रिय भागीदारी रही।

शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे आतंकवादी न बनें: सीएम

आयोजन ● राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई शिक्षाविद हुए शामिल

भोपाल(नवदुनिया प्रतिनिधि)। शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों को ज्ञान और संस्कार मिले। स्कूलों में शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे पढ़कर अच्छा इंसान बनें, न कि आतंकवादी। कोई भी संस्थान अपनी मनमर्जी की शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इन तीनों बातों का पर्याप्त ध्यान रखा है। शिक्षा का अर्थ तोते की तरह रटना, बस्ते के बोझ से दबे रहना नहीं है। शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक और उनकी प्रतिभा का विकास होना चाहिए।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अकादमी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को आयोजित दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मदिन मनाना सौभाग्य मानता हूं। जीवन का आज एक साल कम हो गया। मैंने रोज एक पेड़ लगाने की शुरुआत की है। इस संगोष्ठी में देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र के कार्यकर्ता और नीति-निर्माता शामिल हुए।

प्रशासन अकादमी में दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। साथ में मंच पर उपस्थित हैं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। ● नवदुनिया

शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए: मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए। यह चिंतन होना चाहिए कि शिक्षा का प्रकटीकरण कैसे हो। ज्ञान देने में ज्ञान देने का तरीका कैसा हो, नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से ही नहीं है।

गलती से नहीं बल्कि अपनी पसंद से बनें शिक्षक

शुभारंभ समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. कैलाशचंद्र शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई आयोग बने, नीतियां बनी, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया।

इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए देशभर के शिक्षाविदों ने गंभीर चिंतन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षा प्रणाली के साथ शिक्षकों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गलती से शिक्षक नहीं बनना चाहिए, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने का जज्बा हो तो ही शिक्षक बनना चाहिए। ऐसा होगा तभी एक शिक्षक मन से पढ़ाएगा और आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण करेगा। इस दौरान ऑनलाइन जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने कहा कि शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट है जो भारत को ज्ञान युक्त समाज, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने आधुनिक विज्ञान के उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन आज हमारी शिक्षा सिर्फ लेक्चर सुनने पर केंद्रित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सीखने की चार स्थितियां बताई हैं- पठन, मनन, चिंतन और संकलन। आज आधुनिक विज्ञान इसी प्रक्रिया में सीखने को सबसे अधिक प्रभावी मानता है। दो दिन तक चलने वाली इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 250 से अधिक शिक्षाविद भाग ले रहे हैं।

गांव के रास्ते में सात वर्षीय मासूम

जहां स्वाध्यायी छात्र बैठेंगे वहां पर पिछले वर्ष की तरह लगाया जाएगा अतिरिक्त बल

लगाया जायेगा अतिरिक्त पुलिस बल, हर दिन होगा निरीक्षण

भोपाल(आरएनएन)। अगले मई माह से प्रारंभ हो रही दसवीं बारहवी की परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने हर केन्द्र पर नजर रखने का प्लान तैयार किया है। जिन परीक्षा केन्द्रों पर स्वाध्यायी छात्र बैठ रहे हैं। उन्हें पिछले वर्ष की तरह इस बार भी संवेदनशील की श्रेणी में रखने पर विचार चल रहा है। यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल निगरानी के लिए रखा जाएगा। कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बोर्ड को ऐसे केन्द्रों पर वाद-विवाद की घटनाएं देखने को मिलीं हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जिन सेंटरों पर स्वाध्यायी छात्र बैठेंगें। वहां पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सभी हालातों का जायजा लेने के बाद मंडल के निर्देश पर इन सभी केन्द्रों को पूर्व की तरह संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यहां पर अन्य सामान्य केन्द्रों की अपेक्षा ज्यादा पुलिस बल लगाया जाएगा। ऐसी रणनीति बनाई गई है कि इन हर केन्द्रों पर प्रतिदिन उड़नदस्ता परीक्षाओं की जांच करने के लिए पहुंचेगा। शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडल की जो गाइड लाइन है। उसी के अनुसार विधिवत नियमों का पालन कराते हुए परीक्षाएं प्रारंभ करवाई जाएं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षाओं के लिए हमारी समस्त तैयारियां पूर्ण हैं, लेकिन बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखना भी हमारे लिये बड़ी चुनौती है। भारत सरकार की पूरी गाइडलाइन का केन्द्रों पर पालन करवाया जाएगा।

शुद्ध पेयजल के निर्देश: मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि परीक्षा केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल बच्चों को उपलब्ध कराया जाये। स्कूलों में पानी की टंकियों का परीक्षण करवाया जाये। यदि गंदगी हो तो तत्काल इनकी सफाई हो। ताकि कोरोना का प्रकोप न पनप पाये। परीक्षाओं के दौरान गर्मी पड़ने की संभावना है। इस कारण अभी से निर्देशित किया गया है कि गर्मी के वक्त परीक्षार्थियों के लिए ठंडे पाने की व्यवस्था की जाए। ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने कहा है कि जिन केन्द्रों का अनुमोदन कर मंडल को भेजा गया था। वहां से अनुमोदित सूची आते ही यह तय हो जाएगा कि कितने केन्द्रों पर बोर्ड परीक्षा करवाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मंडल के जो नियम हैं, उसी के अनुसार ही परीक्षाएं संपादित करवाई जाएंगी।

कड़ी सुरक्षा निगरानी में पूर्व की तरह जिलों में भेजी जाएगी परीक्षा सामग्री

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार जिलों में परीक्षा सामग्री भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नियम के अनुसार यह सामग्री भेजी जाएगी। संभवना है कि पूरे मार्च माह तक यह काम चलेगा। बताना होगा कि बोर्ड के तत्कालीन चेयरमेन राधेश्याम जुलानिया ने परीक्षा पद्धति में कई बदलाव किए थे। कुछ दिन पूर्व उनके सभी निर्णय को शासन ने बदल दिया था। दो दिन पूर्व ही जुलानिया की जगह राज्य शासन ने शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी को बोर्ड चेयरमेन का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब उन्हीं के निर्देशन में परीक्षा संबंधी पूरा कार्य हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल अंत से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं की पूरी तैयारियां हैं। पूर्व की तरह नियम के अनुसार पहले उन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होगी, जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा संपन्न हुई होगी । इसके बाद टाइम टेबल के अनुसार क्रमवार कापियों के मूल्यांकन का काम चलेगा। मंडल का कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस की दहशत से सावधान रहने की जरूरत है। इस कारण सभी जिलों में कलेक्टरों एवं सक्षम अधिकारियों से कहा गया है कि वह भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार परीक्षाएं कराने की तैयारी करे। बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षकों को भी परीक्षा समय में सावधानी बरतने का आग्रह करें। क्योंकि काम की व्यस्तता के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्याना देना भी उतना ही जरूरी है। बोर्ड में अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए परीक्षाओं में पूरे इंतजाम होंगे। यदि इसका संक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से दिक्कत उठानी पड़ेगी। इस कारण पहले से ही सतर्क किया गया है। इधर बोर्ड की चेयरमेन ने यहां का प्रभार संभालते ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी नियम प्रक्रिया के साथ काम हो। जिला शिक्षा अधिकारियों ने परीक्षा केन्द्रों की जो सूची भेजी है। उसके अनुसार अपने स्तर पर भी केन्द्रों का अवलोकन करवाया जाए। ताकि निष्पक्ष परीक्षाएं संपादित करवाई जा सकें।

जिला स्तरीय दिव्यांग प्रतियोगिता में बच्चों ने जीते पुरस्कार

शिवपुरी ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला स्तरीय दिव्यांग प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार गत दिवस शिवपुरी मे जनपद शिक्षा केंद्र शिवपुरी माधव चौक प्रांगड मे विकास खंड स्तरीय दिव्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन के पश्चात आज दिनांक 05.03.2021 को जिला स्तरीय दिव्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि द्वारा मां सरस्वती पूजन उपरांत बालिका पूजन कर प्रतियोगिता मे संपन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं मे विजेता एवं भाग लेने वाले दिव्याग बालक बालिकाओं को प्रेरणा स्वरूप पुरुस्कार वितरित किये गए। प्रतियोगिता मे विभिन्न विकासखंडों से लगभग 130 दिव्यांग बालक बालिकाओं ने अपनी क्षमता एवं कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम मे प्रारंभ में ही फल वितरित किये गए। प्रतियोगिता के मध्य मे भोजन वितरण कर कार्यक्रम के अंत मे पधारे हुए समस्त अतिथियों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को पुरुस्कार वितरित किये गये। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दृष्टि दिव्याग शिक्षक रामगोपाल रावत एवं अन्य अतिथि के रूप मे हेमंत ओझा अध्यक्ष भारत विकास परिषद, महेंद्र जैन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,के के शर्मा परियोजना अधिकारी, डीआर कर्ण जिला परियोजना समन्वयक, महेंद्र सिंह तोमर जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरीश शर्मा सहायक परियोजना समन्वयक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी सी अंगद सिंह तोमर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्रतियोगिता आयोजन समिति के सभी सदस्यों का अभूतपूर्व सहयोग रहा ! कार्यक्रम के अंत मे अरविन्द वर्मा बीएसी द्वारा सफल आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया गया।

मध्यप्रदेश में फिर व्यापमं

एक ही कॉलेज से 10 टॉपर, परीक्षा में सभी के अंक और गलतियां भी समान

ग्वालियर। मध्यप्रदेश का व्यापमं एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 2013 का यह मामला देशभर में चर्चित रहा था। लेकिन राज्य में अब एक बार दूसरे व्यापमं घोटाले को लेकर संदेह जताया जा रहा है। दरअसल, मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने वाला मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल जिसे व्यापमं के तौर पर जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इसका कारण है कि व्यापमं की ओर से आयोजित की गई कृषि विस्तार और कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में एक अनोखा संयोग देखने को मिला है। कई लोग इसे दूसरा व्यापमं घोटाला भी बता रहे हैं। इसे संयोग कहा जाए या धांधली कि राज्य भर्ती परीक्षा में एक ही कॉलेज के 10 छात्र टॉप करते हैं। वे सभी शीर्ष 10 में जगह पाते हैं। इन सभी 10 छात्रों के प्राप्तांक भी एक समान है। इतना ही नहीं इन छात्रों की ओर से परीक्षा में की गई गलतियां, त्रुटियां और उनकी जाति भी एक समान हैं। मामला सामने के बाद एक मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से लेकर मध्यप्रदेश सरकार तक हर कोई हैरान -परेशान हैं। दूसरे अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग है कि जांच से पहले इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरे व्यापमं घोटाले की आशंका के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।

मध्यप्रदेश
व्यावसायिक परीक्षा मंडल
(व्यापमं)
व्यापम

फरवरी में हुई थी परीक्षा

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की ओर से 10-11 फरवरी को कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 17 फरवरी को इस परीक्षा की आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। जब परिणाम आया तो पता चला कि वरीयता सूची में शीर्ष 10 स्थान हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी एक ही कॉलेज से हैं।

ग्वालियर के कॉलेज से हैं टॉप 10 छात्र

इन शीर्ष 10 उम्मीदवारों ने राजकीय कृषि कॉलेज, ग्वालियर से बीएससी की पढ़ाई की है। इन्हें परीक्षा में एक जैसे प्राप्तांक मिले हैं और सभी ने परीक्षा में गलतियां भी एक जैसी ही की हैं। इन समानताओं के कारण व्यापमं की भर्ती परीक्षा में धांधली का शक गहरा गया है। इतना ही नहीं इनमें से नौ उम्मीदवार एक ही जाति के हैं। इसे लेकर परीक्षा में शामिल हुए अन्य उम्मीदवारों ने घोटाले का आरोप लगाया है।

सामान्य ज्ञान की परीक्षा में मिले समान अंक

हैरान करने योग्य बात ये है कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की परीक्षा में इन सभी 10 उम्मीदवारों को एक जैसे अंक मिले हैं। गौर करने योग्य यह भी है कि इन टॉपर्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी टॉपर जैसा नहीं है। जानकारी के अनुसार, एक टॉपर उम्मीदवार को गणित में पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, जबकि बीएससी की परीक्षा के दौरान वह सांख्यिकी विषय में चार बार फेल हो चुका है। उसने डिग्री आठ साल में पूरी की थी। चौंकाने वाले बात यह भी है कि इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए हैं, वे भी एक जैसे हैं। फिर भी वे टॉपर हैं।

ब्लैकलिस्टेड कंपनी एनएसईआईटी ने कराई थी परीक्षा

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की ओर से इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी एनएसईआईटी कंपनी को दी थी। यह कंपनी पहले भी धांधली के आरोपों से घिरी रही है। 2017 में उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते एनएसईआईटी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। इस बार टॉप 10 में शामिल उम्मीदवारों को 200 में 195 और 194 अंक मिले हैं, इस परीक्षा के इतिहास में इतने नंबर किसी को नहीं मिले। खैर, मुख्यमंत्री शिवराज ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

तक्षशिला के 5 छात्रों का हुआ सिविल इंजीनियरिंग में चयन

ऋषीश्वर कंस्ट्रक्शन ने लगाया क्लोज कैम्पस

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशंस में ऋषीश्वर कंस्ट्रक्शन प्रालि. कंपनी का सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए कैम्पस का आयोजन किया गया। कैम्पस के दौरान कंपनी के एचआर धीरज शर्मा ने साक्षात्कार द्वारा 5 छात्रों का चयन कर छात्रों को ऑफर लेटर प्रदान किए गए।

इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन एससी मसुरहा ने कहा कि गत कई वर्षों से संस्था में कैम्पस के माध्यम से छात्रों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। कैम्पस के दौरान पीके तिवारी, रतन खर्द, शरद गुप्ता, ग्रुप डायरेक्टर आई के खन्ना, अर्पित शुक्ला, विशाल सक्सेना प्राचार्य बीके साहू के साथ प्राध्यापकगणों ने छात्रों के भविष्य की उज्जवल कामना की।

एक दिन की SDM बनकर बोली सोना-अब खूब करूंगी पढ़ाई

9वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी सोना का बढ़ा मनोबल, अब सीखेगी सिलाई-कढ़ाई, अगले सत्र में स्कूल में भी दाखिला लेगी

विनय शुक्ला ● शहडोल
मो.नं. 9407813266

पीपुल्स समाचार स्पेशल

एसडीएम की कुर्सी पर बैठी सोना, साथ में एसडीएम प्रियांशी भंवर और सोना की मां।

ब्यौहारी तहसील की एसडीएम प्रियांशी भंवर ने ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को सबल और उन्हें शिक्षित करने के लिए अपनी पहल 'मिशन तेजस्विनी' के तहत गुरुवार को एक 18 साल की बालिका को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया।

उनकी इस पहल से बच्ची का मनोबल बढ़ा और सोना चर्मकार नाम की इस बेटी अब आगे खूब पढ़ाई करने का मन बना लिया है। सोना का कहना है कि 9वीं फेल होने के बाद पढ़ाई की इच्छा छूट चुकी थी। मैडम ने मनोबल बढ़ाया है इसलिए अब आगे खूब पढ़ाई करूंगी। मेरा प्रयास रहेगा की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई उच्च पद प्राप्त करूं। सोना ने बताया कि एक दिन की एसडीएम बनने के बाद एसडीएम का काम करीब से देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। कई जगह जाकर कामों का निरीक्षण भी किया।

मजदूरी करते हैं माता-पिता

जानकारी के अनुसार, सोना पिता मंगल प्रसाद चर्मकार (18), ब्यौहारी के ग्राम झरौंसी की रहने वाली है। वह 27 फरवरी ब्यौहारी एसडीएम प्रियांशी भंवर से मिली थी। बातचीत में एसडीएम को पता चला कि वह तीन वर्ष पूर्व, 9वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी है। सोना ने यह भी बताया कि, उसके माता-पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार की स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने बच्ची को उसकी मां के साथ दोबारा 1 मार्च को बुलवाया और समझाइशदी। इसके बाद गुरुवार को एक दिन का एसडीएम बनाया।

प्रशासनिक कार्यों को जाना, SDM के साथ खाना खाया

एसडीएम प्रियांशी भंवर ने बताया कि सोना को कार्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसके बाद सोना को अपने निवास पर ले जाकर दोपहर का भोजन करवाया और नगर परिषद ब्यौहारी के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कराया। एसडीएम द्वारा एनआरएलएम को निर्देशित किया कि, अगले माह में बालिका को वोकेशनल एजुकेशन के तहत सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दें एवं अगले शैक्षणिक वर्ष में उसे पुनः स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए बीईओ को निर्देशित किया है।

फेसबुक पर संपर्क कर सकती हैं बच्चियां: प्रियांशी

एसडीएम प्रियांशी भंवर ने 'पीपुल्स समाचार' से हुई बातचीत में बताया कि, तेजस्विनी नामक इस कार्यक्रम की शुरूआत मैंने छतरपुर में किया था। इसके बाद यहां पर ट्रांसफर होकर आई, तो यहां भी इसकी शुरूआत की है। जिसका उद्देश्य बच्चियों में आत्मविश्वास को जगाकर उन्हें सबल और शिक्षित बनाना है। पहले हम 10वीं व 12वीं की टॉपर लड़कियों को चयनित करते थे, लेकिन अब चयन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है।

मॉडल स्कूल में ओजस यूथ क्लब की कार्यशाला आयोजित

पीपुल्स संवाददाता ● दमोह

मो.नं. 8435502322

ओजस यूथ क्लब शासकीय मॉडल विद्यालय में जिला बाल अधिकार मंच के सहयोग से 'स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी' विषय बौद्धिक गतिविधियों के तहत नाट्य कार्यशाला आयोजित हुई। पहले दिन दमोह के प्रतिष्ठित वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ मंच के वरिष्ठ सदस्य डॉ. संजय त्रिवेदी का व्याख्यान आयोजित किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने बच्चों के लिए दैनिक दिनचर्या व आहारचर्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको स्वच्छ रहकर विद्यालय को भी स्वच्छता बनाए रखना है।

कॉलेज में आत्मरक्षा के लिए दी जा रही बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

पीपुल्स संवाददाता ● शहडोल

editor@peoplessamachar.co.in

पंडित एसएन शुक्ला विवि शहडोल मप्र में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा छात्राओं को तीन दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलाई जा रही है।

महिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि, आए दिन लड़कियों-महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं। कानून बेशक अपना काम करता है लेकिन, इन घटनाओं पर अंकुश लगे। इसके लिए बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वे खुद उसका जवाब दे सके।राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस के परिपेक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का शुक्रवार को पहला दिन था। जिसमें तकरीबन 20 छात्राएं सम्मिलित हुईं। जिसमें छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सुनक्षात्मक तरीकों को जाना, समझा और अभ्यास किया। प्रशिक्षण का समापन राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को कॉन्फ्रेंस हाल में किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में मोनू जैसवाल, साक्षी गुप्ता, गजाला अख्तर, दरक्शा बानो, शीतल शुक्ला एवं रासेयो के स्वयंसेवकों की सहभागिता रही।

महिलाओं को पांच सरकारी पुरस्कार देने का वक्त नहीं

दो साल से महिला बाल विकास विभाग ने नहीं की पुरस्कारों की घोषणा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाते हैं पांच महिला पुरस्कार

भोपाल ■ श्रवण मावई

अदम्य साहस, बहादुरी और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला बाल विकास विभाग हर साल पांच अलग-अलग पुरस्कारों से महिलाओं को नवाजता है। यह पांच पुरस्कार साहसिक और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली नायिकाओं के नाम से आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाते हैं, लेकिन दो साल से यह पुरस्कार देने की फुरसत किसी को नहीं है। यहां तक कि बीते वर्ष तो चयन समिति तक नहीं गठित हुई। इस साल अब तक आवेदन की तारीख ही घोषित नहीं की गई है। इससे साफ है कि इस वर्ष महिलाओं को मिलने वाले राज्य स्तरीय पांचों बड़े पुरस्कार महिला दिवस पर नहीं दिए जाएंगे।

राज्य शासन ने अलग-अलग वर्ष में महिलाओं के लिए पांच पुरस्कारों देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इनके अनुसार अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार 2016, राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2017, मुख्यमंत्री नारी रक्षा सम्मान 2011, राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरस्कार 2006 और रानी अवंतिबाई वीरता पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। यह पांचों राज्य स्तरीय पुरस्कार साल 2020 में नहीं दिए गए। हालांकि विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन आठ मार्च महिला दिवस तक चयन समिति ही गठित नहीं की गई जिससे नाम चयन नहीं हुए। वहीं साल 2021 में अब तक महिला बाल विकास विभाग ने आवदेन तक आमंत्रित नहीं किए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है यह अधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को ढाल के रूप में सामने कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश में अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं।

(शेष - पेज 8 पर)

पात्र महिलाएं नहीं करती आवेदन

विभाग के अनुसार पुरस्कार के लिए पात्र आवदेनकर्ता नहीं मिलते हैं। साहसिक कार्य करने वाली महिलाएं आवेदन नहीं करती, जिससे बीते कई सालों से नाम चयन करने में कठिनाई होती है। विभाग की इस बात से लगता है कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों का प्रचार-प्रसार ठीक से नही होता है। महिलाओं को जानकारी के अभाव में पात्र आवेदन विभाग तक नहीं पहुंचते हैं।

यह भी विडंबना

केंद्र सरकार हर साल राष्ट्रीय स्तर पर नारी वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष इन पुरस्कारों में मध्यप्रदेश की एक भी महिला का नाम चयनित नहीं हुआ। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए मप्र की कुछ महिलाओं ने आवेदन किए थे।

किसके नाम पर पांच पुरस्कार

1) अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार

मुबंई के एक अस्पताल में नर्स अरुणा शानबाग के साथ 1973 में वहां काम करने वाले सोहनलाल ने कुत्ते की चेन से बांध कर रेप किया और मरणासन अवस्था में छोड़कर चला गया था। लगभग 42 साल तक अरुणा शानबाग अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। साल 2015 में अरुणा शानबाग ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हीं के नाम साल 2016 में मप्र सरकार ने अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार के लिए चयनित महिला को एक लाख रुपए और प्रशास्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार के लिए 10 जनवरी तक आवदेन करना होता है। चयन समिति 15 फरवरी तक नाम की घोषणा करती है और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंलकरण समारोह आयोजित कर पुरस्कार दिया जाता है।

4600 कोचिंग, 7 लाख बच्चे, ये कोटा के बाद सबसे ज्यादा, 140 सीबीएसई स्कूल, अब 2 इंटरनेशनल लेवल के स्कूल भी आएंगे

इंदौर का एजुकेशन न केवल आईआईटी और आईआईएम यहां, बल्कि इंजीनियरिंग के दो श्रेष्ठ संस्थान आईईटी और एसजीएसआईटीएस भी यहीं

भास्कर संवाददाता | इंदौर

एजुकेशन सेक्टर में इंदौर ने 10 साल में बड़ी तेज रफ्तार से तरक्की की है। आईआईएम, आईआईटी एक ही शहर में होने का गौरव हासिल करने वाले इंदौर में अब 4600 से अधिक छोटी-बड़ी कोचिंग क्लासेस हो गई है, जिनमें करीब 7 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये टू टियर सिटी में कोटा के बाद सबसे अधिक है। खास बात ये है कि कोटा में कोचिंग के बाद बच्चों को दूसरे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, लेकिन इंदौर में उनके लिए आईआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, सिम्बॉयसिस, नरसी मुंजी, वैष्णव, देवी अहिल्या सहित 10 बड़ी यूनिवर्सिटी, 55 से अधिक इंजीनियरिंग और 3 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अवसर रहते हैं। इसकी वजह से अब देश के कई राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए इंदौर आ रहे हैं। पहले सिर्फ मध्य के बच्चों के लिए ये बड़ा केंद्र था, अब राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दक्षिण भारत के राज्यों के बच्चे यहां करियर बनाने के लिए आते हैं। वे यहां न सिर्फ प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे, बल्कि स्कूलिंग भी यहीं से करने लगे हैं। शहर में 140 सीबीएसई स्कूल हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई करवा रहे हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चे एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत यूरोप, अमेरिका के बड़े स्कूलों में पढ़ने जाते हैं।

एजुकेशन एक्सपर्ट के मुताबिक, अगले दो साल में सांवेर रोड और बायपास पर दो बड़े इंटरनेशनल स्कूल आने के बाद इंदौर नेक्स्ट लेवल पर होगा। कई बड़े स्कूल विस्तार की योजना बना रहे हैं तो कुछ मेडिकल कॉलेज भी यहां आने की तैयारी में हैं।

सिमरोल स्थित 500 एकड़ में फैला आईआईटी का कैंपस। यहां मुख्य प्रशासनिक भवन 'अभिनंदन' तैयार हो चुका है। इसके अलावा अन्य निर्माण कार्य भी चल रहे हैं।

रैंकिंग में मुंबई को पीछे छोड़ चुका इंदौर आईआईटी

शहर में जितने भी बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, वे सब आला दर्जे के हैं। आईआईटी में 40 कोर्स संचालित हो रहे हैं और यह एक दफा रैंकिंग में आईआईटी मुंबई को पीछे छोड़ चुका है। अभी यहां 2200 छात्र हैं। आने वाले समय में इसकी क्षमता चार हजार छात्रों की हो जाएगी। आईआईएम देश का दूसरा ऐसा इंस्टिट्यूट है, जिसके पास ट्रिपल क्राउन है। रैंकिंग में ये देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थान में शामिल है। इसका बेच साइज सबसे बड़ा है। आईआईएम इंदौर 12वीं बाद आईपीएम कोर्स शुरू करने वाला भी पहला संस्थान है।

शहर में 1000 होस्टल, 2.5 लाख छात्र रहते हैं यहां

इतने सारे शैक्षणिक संस्थान के चलते शहर में एक हजार होस्टल खुल गए हैं। इसके अलावा इंदौर से बेहतर रोड और हवाई कनेक्टिविटी के कारण छात्रों के लिए यहां रहना और आना-जाना मुश्किल नहीं होता।

प्रदेश के दो बड़े इंजीनियरिंग संस्थान भी इंदौर में

इंदौर के साथ एक और उपलब्धि जुड़ी हुई है कि यहां प्रदेश में इंजीनियरिंग के दो श्रेष्ठ संस्थान आईईटी (इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) और एसजीएसआईटीएस (श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस) मौजूद हैं। एसजीएसआईटीएस प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हैं। रिसर्च के मामले में ये देश में टॉप 20 में शामिल है। बड़ी औद्योगिक समूह यहां से रिसर्च वर्क करवाते हैं। कई कंपनियों के प्रोडक्ट भी यहीं से प्रमाणित हुए हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवाएगी अलग पहचान

प्रबंधन और तकनीक के श्रेष्ठतम संस्थानों के साथ इंजीनियरिंग संस्थानों की शृंखला इंदौर को सबसे अलग रखती है। अब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकारी प्रयासों की भी जरूरत है।

- पुरुषोत्तमदास पसारी, कुलाधिपति, श्री वैष्णव विद्यापीठ विवि इंदौर

हमारी शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जोड़ना चाहिए

कोरोना ने हमें शिक्षा में भी नया करने का मौका दिया। आने वाला समय पूरी तरह से ना ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यह हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों को अपने से जोड़ने का मौका देगा।

- अचल चौधरी, प्रिंसिपल, आईपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशंस

सहकारिता विभाग में जूनियर सेल्समैन की ज्वॉइनिंग का मामला

दस्तावेज सत्यापित, भोपाल से होगी नियुक्ति

ग्वालियर• डीबी स्टार

सहकारिता विभाग में जूनियर सेल्समैन के 3629 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद अब चुने गए आवेदकों की ज्वॉइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। आवेदकों के दस्तावेज सत्यापित कर भोपाल भेज दिए हैं। अब वहीं से इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे।

डीबी स्टार ने 26 फरवरी के अंक में "ऑनलाइन मेरिट वाले इंतजार करते रह गए, ऑफलाइन दे दी दूसरों को नौकरी' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया था कि सहकारिता विभाग में 3629 पदों पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन उन्हें अब तक नौकरी पर ज्वॉइन नहीं करवाया गया। चुने गए आवेदकों की हड़ताल और प्रदर्शन के बाद सहकारिता मंत्री ने 10 फरवरी से इनका दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए कहा

ऑनलाइन मेरिट वाले इंतजार करते रह गए, ऑफलाइन दे दी दूसरों को नौकरी

डीबी स्टार में गत 26 फरवरी को प्रकाशित खबर।

था, लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया ही नहीं गया। पूछने पर पता चला कि उनके स्थान पर ऑफलाइन ही किसी अन्य अभ्यर्थी को नौकरी पर रख लिया गया था। राशन की दुकानों पर ऑपरेटर की तरह काम करने के लिए आवेदन करने वाले इन आवेदकों की परेशानी डीबी स्टार में खबर के तौर पर प्रकाशित होने के बाद सहकारिता विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी सहकारियों विभाग के अधिकारियों ने मेरिट वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित करना शुरू कर दिया है।

आरजीपीवी • अभी तक औसत पैकेज 12 लाख का होता था, इस बार हुआ इजाफा

कोरोना काल में 7000 छात्रों का ऑनलाइन प्लेसमेंट, सबसे बड़ा पैकेज 19 लाख का

मेरा करियर

ग्वालियर/भोपाल • डीबी स्टार

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) से संबद्ध कॉलेजों के पास आउट छात्रों की प्लेसमेंट प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अब तक इंजीनियरिंग के 7000 स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिल चुके हैं। इनमें से 5000 ने तो नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। ये सभी प्लेसमेंट कोरोना काल में ही हुए हैं। फिलहाल, दस से अधिक मल्टी नेशनल कंपनियों की ऑनलाइन प्लेसमेंट प्रक्रिया जारी है, जबकि अगले माह से 12 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां आने वाली हैं। अभी तक प्रक्रिया में इंजीनियरिंग का सालाना पैकेज औसतन 12 लाख होता था, लेकिन इस बार 19 लाख रुपए तक यह पहुंच गया है। आरजीपीवी के संबद्ध कॉलेजों में आंकड़ा भले ही बेहतर हो, लेकिन आरजीपीवी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हाल थोड़ा खराब हुआ है। वर्ष 2019-20 में जहां 271 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला था तो वहीं इस साल यह आंकड़ा 184 पहुंचा है।

नौकरी और पैकेज

आरजीपीवी	2020	2021
जॉब मिली	271	184
औसत पैकेज	12 लाख	10 लाख
कंपनी संख्या	51	52
मैनिट	**2020**	**2021**
जॉब मिली	628	360
औसत पैकेज	16 लाख	10.5 लाख
कंपनी संख्या	162	80

इस साल 13 हजार छात्रों ने कराया था जॉब के लिए पंजीयन

आरजीपीवी में तीन साल में 12-13 हजार छात्रों को जॉब ऑफर्स आते रहे हैं। पिछले साल मार्च में कोरोना संकट शुरू हुआ तो चार महीने तक प्लेसमेंट प्रक्रिया रुक गई। कुछ कंपनियों ने ऑनलाइन प्लेसमेंट प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सितंबर महीने से इसमें तेजी आई और इस साल 13 हजार छात्र-छात्राओं ने पंजीयन करवाया और इनमें से 7000 को नौकरी मिल गई। यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

तीन महीने में ही पूरा हो गया टारगेट

आरजीपीवी की प्लेसमेंट ऑफिसर शिखा अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संकट के बावजूद 7000 का आंकड़ा पार करना बड़ी बात है। तीन महीने में ही सालाना टारगेट पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि यह जॉब इसलिए मिल रहे हैं कि हम बच्चों को कंपनी के आने से पहले ही ट्रेनिंग देकर तैयार कर देते हैं। हमारा फोकस अमेजन, फेसबुक, गूगल और अन्य डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों पर अधिक है।

भास्कर

यूजीसी नेट की बढ़ाई तिथि, अब 9 तक जमा होंगे ऑनलाइन आवेदन

विद्यार्थियों को राहत

सिटी रिपोर्टर | नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें एनटीए ने राहत देते हुए कुछ और दिनों का मौक दिया है। इसके अनुसार अब वे आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर एनटीए ने वेबसाइट पर नोटिफिक्केशन जारी किया है।

दो पाली में होंगे पेपर

यूजीसी नेट परीक्षा 2 मई, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, और 17 मई को आयोजित किया जाना है। यह परीक्षा तीन घंटे की होगी। इसमें दो पेपर होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली के पेपर सुबह 9:30 से दोपहर के 12:30 तक होंगे। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।

ये रहेगा शेड्यूल

- आवेदन की अंतिम तिथि- 9 मार्च
- शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 10 मार्च
- करेक्शन विंडो- 12 से 16 मार्च तक ओपन रहेगी।

स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारियों का केंद्र बन रहा इंदौर; हर साल एक लाख से ज्यादा छात्र तैयारी करते हैं

भास्कर संवाददाता | इंदौर

इंदौर शहर स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारियों का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहां हर साल एक लाख छात्र पीएससी आदि परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आते हैं। इसका नतीजा है कि हर साल सात से आठ नए कोचिंग संस्थान और होस्टल खुल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं का रुझान खासकर पीएससी का कम हो गया था। इसके कई कारण हैं, लेकिन इस साल पीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या में अचानक से इजाफा होने जा रहा है।

पीएससी की तैयारी कर रहे ज्यादातर छात्र बीए में एडमिशन ले रहे हैं। यह चलन शुरू से था, लेकिन अब बढ़ोतरी हो गई है। पिछले साल भी नए एडमिशन में बीए आगे था। इस बार बीकॉम की तुलना में बीए में 31 हजार ज्यादा छात्र हैं।

बीए में स्पेशलाइजेशनः पीएससी की तैयारी से जुड़े कोर्स ज्यादा आ रहे

निजी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ललित सिंह जादौन कहते हैं कि अब बीए में सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन कोर्स आ रहे हैं। खास कर पीएससी की तैयारी से जुड़े कोर्स ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि होलकर कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉ. संजय व्यास कहते हैं कि बीएससी कोर्स की डिमांड अभी भी बरकरार है। खासकर कॉम्बिनेशन वाले कोर्स पर छात्रों का ज्यादा फोकस है। सीनियर प्राचार्य डॉ. संगीता भारूका कहती हैं कि बीकॉम भी अपनी जगह स्थिर है, लेकिन अब बीकॉम में जॉब ओरिएंटेड नए स्पेशलाइजेशन कोर्स की दरकार है। अन्यथा आगे संख्या पर असर पड़ सकता है।

इंदौर का बैग कारोबार • 25 साल पहले शुरू हुआ कारखाना, 350 से अधिक कर्मी, इनमें 60% महिलाएं

कपड़े के झोले बनाने से किया काम शुरू, आज उनके बनाए बैग के खरीदार इंटरनेशनल ब्रांड

सालाना टर्नओवर 40 करोड़ का

» अब उनके 90 फीसदी से अधिक बैग्स और अन्य सामग्री एक्सपोर्ट हो रही अमेरिका और यूरोप में

» उसके खरीदार टॉमी हिलफिगर, अमेरिकन टूरिस्टर जैसे ब्रांड

» देश-दुनिया की 100 से ज्यादा छोटी-बड़ी कंपनियों के साथ कारोबारी करार

सुमित ठक्कर | इंदौर

अन्नू माहेश्वरी ने 1995 में जब कपड़े के झोले बनाने का काम शुरू किया तो उन्हें भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि एक दिन उनका कारोबार इस ऊंचाई तक पहुंचेगा कि दुनिया के सारे बड़े ब्रांड उनके साथ काम करेंगे। आज सैमसोनाइट, वीआईपी, सफारी ही नहीं, टॉमी हिलफिगर, अमेरिकन टूरिस्टर भी अन्नू की कंपनी के बैग के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है।

उनके बैकपैक, डफल, बिजनेस और प्रोफेशनल बैग की डिमांड पूरी दुनिया के बड़े ब्रांड को है। यूरोप व अमेरिका की कई कंपनियां उनके बैग खरीदती हैं, जो उनके ब्रांड का टैग लगकर बिक्री के लिए बाजार में आते हैं। अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड उनके बैग के बड़े खरीदार हैं। अन्नू बताती हैं होम साइंस में पढ़ाई की थी, इसलिए सिलाई-कढ़ाई जैसे कामों में शुरू से रुचि थी। शादी के बाद पति का फिल्ट्रेशन का बिजनेस देखा तो खुद कुछ अलग करने का सोचा। परिवार का सपोर्ट मिला और इस काम में आगे बढ़ती गई। झोले से बैक पैक के 40 करोड़ टर्नओवर तक के सफर का संघर्ष और मेहनत मेरे लिए खुद किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं।

इंटरनेशनल ट्रेड शो का बने हिस्सा

- फास्ट ट्रैक, डुकाती, स्कायबैग, नॉर्थ स्टार, बेवरेली हिल्स, पॉवर, हेड, एचआरएक्स जैसी कंपनियों के साथ हैं अन्नू की कंपनी का करार।
- कोरोना को देखते हुए बड़े पैमाने पर पीपीई किट, ग्लव्ज, मास्क, फेसशील्ड, शू कवर आदि भी बनाए हैं।
- लॉस वेगास, बर्लिन, हनोवर, सिडनी, हांगकांग, टोक्यो, साओपाउलो के इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी अन्नू की कंपनी के बैग्स प्रदर्शित हुए हैं।
- कंपनी हर महीने 70 हजार बैकपैक, 15 हजार डफल और बिजनेस बैग व 1 लाख प्रमोशनल बैग बना रही है।

यूनिट में 24 घंटे चलता काम

आईएफएफ ओवरसीज के साथ 100 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। कंपनी की संचालक अन्नू माहेश्वरी बताती हैं कि मूसाखेड़ी में उनकी यूनिट है, जहां 350 से अधिक कारीगर हैं। इसमें भी 60 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं।

डीएवीवी: ऑटोमेशन करने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, अब हमेशा होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं

सक्सेस मॉडल

दिनेश जोशी | इंदौर

एजुकेशन हब के तौर पर पहचान बना चुका इंदौर अब 2021-22 में ऑटोमेशन की ओर बढ़ेगा। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के 12 मॉड्यूल में से परीक्षा संबंधी चार का ट्रायल शुरू हो गया है।

इस साल जुलाई से यह इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (आईयूएमएस) का पहला चरण लागू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूनिवर्सिटी सभी परीक्षाओं के परचे सेंटर पर ऑनलाइन भेज सकेगी। सेंटर से एक क्लिक पर प्रिंट आउट निकालकर परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। पर्चे लेकर आने-जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा।

यूनिवर्सिटी दूसरे चरण में 1 जनवरी 2022 से एमबीए, बीसीए, बीबीए और बीए एलएलबी जैसे कोर्स की पहले सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करेगी। फिर धीरे-धीरे सारे प्रोफेशनल कोर्स में यह सिस्टम लागू होगा। फिलहाल कोरोना संकट के कारण यूनिवर्सिटी ने बीए एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम की कुछ परीक्षा ऑनलाइन करवाई, जो काफी हद तक सफल रहीं। तक्षशिला परिसर के 30 टीचिंग विभागों में तो बाकायदा 2021 में 199 कोर्स के प्रथम सेमेस्टर की सभी परीक्षा मार्च में ऑनलाइन करा रही है। यह सफल रहा तो यहां यह सिस्टम स्थायी लागू हो जाएगा।

एक क्लिक पर यूनिवर्सिटी की हर सुविधा का फायदा

छात्रों को भी महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। छात्र को सिर्फ एडमिशन के समय एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर छात्र को पूरी पढ़ाई के दौरान घर बैठे एक क्लिक पर यूनिवर्सिटी की हर सुविधा का फायदा मिलेगा। एक क्लिक पर छात्र न केवल अपनी सारे सेमेस्टर की मार्कशीट घर बैठे देख सकेगा, बल्कि एक ही पासवर्ड से वह डिग्री, माइग्रेशन के लिए भी घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। अभी छात्र को हर बार, हर प्रक्रिया के लिए नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।

288 संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के 3 लाख 3 हजार छात्रों को मिलेगा फायदा।

880 मूल्यांकनकर्ताओं को फायदा।

14 हजार 500 यूटीडी के छात्रों की भी राह होगी आसान।

45 विभाग यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़े ऑटोमेशन से जुड़ जाएंगे।

फायदा: छात्रों और टीचर को

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी बताते हैं कि इस सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा छात्रों और टीचिंग स्टाफ को मिलेगा। परीक्षा और रिजल्ट का अलग मॉड्यूल बनेगा, जिससे यहां का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। इसमें छात्र किसी भी सर्विस के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेगा। वह भी बिना किसी अन्य एजेंसी की सहायता के वह यह प्रक्रिया कर सकेगा। उसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे कहते हैं इससे यूनिवर्सिटी के सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।

सिस्टम: होगा ऑनलाइन

इस सिस्टम में यूनिवर्सिटी के हर एक सेक्शन को इस ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए छात्रों को क्वालिटी और समय पर सर्विस मिल सकेगी। इसके लिए हर एक काम के लिए समय भी तय रहेगा। इस सिस्टम में हर सेक्शन का एक अलग माड्यूल होगा, जिसे आपस में जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की तर्ज पर यह भी काम करेगा।

ऐसे बढ़ता गया दायरा - दरअसल, 2011 के बाद इंदौर में निजी यूनिवर्सिटी की डिमांड तेजी से बढ़ी। इसके बाद ही वैष्णव विद्यापीठ, रेनेसां, सिम्बायोसिस, एपीजे अब्दुल कलाम, मेसीकेप्स, मालवांचल, सेज जैसी यूनिवर्सिटी खुलती गईं। नरसीमुंजी जैसे ऑफ कैम्पस (एक तरह की यूनिवर्सिटी ही) भी शुरू हुए।

एजुकेशन हब : 2023 तक इंदौर में होंगे 4 लाख छात्र

एजुकेशन हब इंदौर में 2023 तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या चार लाख पार होगी। वर्तमान में डीएवीवी से संबद्धता प्राप्त 291 कॉलेज हैं, जिनमें 3 लाख 3 हजार छात्र हैं। इनमें 1 लाख 1 हजार छात्र दायरे में आने वाले अन्य जिलों के हैं। शहर में 2 लाख 1 हजार और 14 हजार छात्र यूटीडी में हैं, जबकि 49 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 72 हजार छात्र हैं। 13 हजार छात्र फार्मेसी और 12 हजार मेडिकल कोर्स (बीएससी नर्सिंग, बीफार्मा व अन्य) के हैं। आईआईटी, आईआईएम और 9 निजी यूनिवर्सिटी में 18 हजार छात्र हैं। इस तरह 3 लाख 30 हजार छात्र हैं। दो साल में यह संख्या चार लाख पार पहुंचने का अनुमान है।

रोजगार के अवसर: यूनिवर्सिटी के छात्रों का टॉप मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही ऑनलाइन प्लेसमेंट

कोरोना काल में यूनिवर्सिटी के साथ ही निजी और सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसे स्थायी व्यवस्था के तौर पर लागू करने की तैयारी है। शिक्षाविद् डॉ. गणेश कावड़िया कहते हैं यूटीडी और कॉलेजों के साथ ही कई निजी यूनिवर्सिटी में 400 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन कोर्स चल रहे हैं। इनमें से 120 तो ऐसे हैं, जो देश में कहीं नहीं हैं। अंग्रेजी और कम्युनिकेशन विशेषज्ञ डॉ. रीमा चौधरी कहती हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों के छात्र भी इंदौर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कोरोना में भी यह सिलसिला थमा नहीं है। शिक्षाविद् डॉ. कविता कासलीवाल कहती हैं कि आने वाले दिनों में छात्रों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी से बढ़ाना होगा। इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर डॉ. प्रीति दुबे कहती हैं कि निजी यूनिवर्सिटी और ऑफ कैम्पस में लगातार सीटें बढ़ रही हैं और नए एडमिशन की संख्या बढ़ रही है।

3 साल में सारी परीक्षाएं-मूल्यांकन ऑनलाइन होंगे

दरअसल, यूनिवर्सिटी की तैयारी है कि बीकॉम, बीए और बीएससी के दो लाख छात्रों सहित सारे तीन लाख 4 हजार छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाए। इनका मूल्यांकन भी ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। इससे यूनिवर्सिटी का समय बचेगा और प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के पास फिलहाल सारे छात्रों का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में यह डेटा और अपडेट होगा, ताकि बेहतर तरीके से वह एडमिशन से डिग्री तक की प्रक्रिया पूरी कर सके।

भास्कर

109 साल पुरानी गवर्नमेंट प्रेस बंद होगी, इमारत स्मार्ट सिटी को मिलेगी

159 कर्मचारियों को दिए जाएंगे दूसरे दफ्तरों के विकल्प

सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर

महाराज बाड़ा स्थित 109 साल पुरानी गवर्नमेंट प्रेस जल्द बंद कर दी जाएगी। सिंधिया रियासत द्वारा 1912 में स्थापित इस प्रेस में जयाजी प्रताप अखबार प्रकाशित, राज्य के हुक्मराने और गजट आदि का प्रकाशन होता था। बाद में यहां निर्वाचन की गोपनीय सामग्री सहित सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किया जाने लगा। अभी यहां नगरीय निकाय चुनाव की पीठासीन व सेक्टर अधिकारियों की 30 हजार डायरियों का प्रकाशन व जिल्दसाजी का काम चल रहा है। बाड़ा सहित इंदौर, रीवा के गवर्नमेंट प्रेस बंद करने का आदेश गुरुवार को कर दिए गए। प्रेस के कर्मचारियों की पद स्थापना को लेकर आठ सदस्यीय संभाग स्तरीय कमेटी बनी है। इसमें अध्यक्ष संभाग आयुक्त होंगे जबकि सदस्य के रूप में कलेक्टर, जिला पंजीयक, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, नियंत्रक गवर्नमेंट प्रेस द्वारा मनोनीत कोई तीन सदस्य रहेंगे। सचिव के रूप में भी गवर्नमेंट प्रेस के अधिकारी को तैनात किया जाएगा।

नीलाम की जाएगी संपत्ति

गवर्नमेंट प्रेस महाराज बाड़ा की बिल्डिंग को स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने मांगा है। इसके अलावा जो भी और संपत्ति होंगी, उन्हें नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। गवर्नमेंट प्रेस परिसर का स्वामित्व राजस्व विभाग के पास ही रहेगा।

प्रदेश में 495 खाली पद खत्म किए गए

ग्वालियर सहित इंदौर व रीवा के गवर्नमेंट प्रेस में कुल 1286 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 495 अभी खाली हैं। इन खाली पदों को सरकार ने खत्म कर दिया है। वर्तमान में काम कर रहे 67 कर्मचारियों को राजस्व विभाग में भेजा जाएगा। कुल 185 पदों को सांख्येत्तर रखा गया है। कुल 114 श्रेणी के पदों को 13 श्रेणियों अर्थात 8 तकनीकी एवं 5 गैर तकनीकी में रखा जाएगा। भविष्य में सिर्फ 7 श्रेणियों के खाली पद ही भरे जाएंगे।

आलीजाह दरबार टोकन आज भी प्रचलित

गवर्नमेंट प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि वर्तमान में काम करने वाले जो कर्मचारी अनपढ़ हैं उन्हें हाजिरी लगाने के लिए आज भी सिंधिया रियासत की तरह आलीजाह दरबार के नाम से टोकन दिए जाते हैं। इसी से काम का हिसाब लगाकर उनका वेतन निकाला जाता है।

सरकार के दस्तावेज किए जाते थे प्रिंट

1912 में गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। पहले यहां जयाजी प्रताप अखबार सहित सरकार के सभी दस्तावेज छापे जाते थे जो बाद में मप्र संदेश के नाम से प्रिंट होने लगा था। **-रमाकांत चतुर्वेदी,** पुरातत्वविद

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स • रैंकिंग के लिए 111 शहरों के 32 लाख लोगों की राय ली गई

बसने के लिए बेंगलुरू सबसे अच्छा शहर, इंदौर नगर निगम टॉप पर, भोपाल तीसरा

एजुकेशन में चंडीगढ़, हेल्थ में औरंगाबाद टॉप पर

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से शहरों की रैंकिंग जारी की। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरू और पुणे रहने के लिए सबसे बेहतर शहर माने गए। जबकि, श्रीनगर और धनबाद सबसे निचले पायदान पर रहे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाने के लिए 111 शहरों के कुल 32 लाख लोगों से भी राय ली गई। इनमें 13 लाख लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए राय दी। शहरों के आकलन के लिए कुल 21 मानक तय किए गए थे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था, मनोरंजन और आर्थिक अवसर जैसे मानक प्रमुख हैं। इसी तरह नगर निकायों की परफॉर्मेंस के आधार पर भी शहरों की रैंकिंग की गई। इनमें इंदौर पहले, सूरत दूसरे और भोपाल तीसरे स्थान पर रहा। इसके मानक सर्विस, वित्तीय स्थिति, तकनीक, योजनाएं और प्रशासनिक व्यवस्था हैं।

10 लाख से ज्यादा आबादी

रैंकिंग	शहर	स्कोर
1.	बेंगलुरू	66.70
2.	पुणे	66.27
3.	अहमदाबाद	64.87
4.	चेन्नई	62.61
5.	सूरत	61.73
6.	नवी मुंबई	61.60
7.	कोयम्बटूर	59.72
8.	वडोदरा	59.24
9.	इंदौर	58.58
10.	ग्रेटर मुंबई	58.23

10 लाख से कम आबादी

रैंकिंग	शहर	स्कोर
1.	शिमला	60.90
2.	भुवनेश्वर	59.85
3.	सिल्वासा	58.43
4	काकीनाडा	56.84
5.	सेलम	56.40
6.	वेल्लोर	56.38
7.	गांधीनगर	56.25
8.	गुरुग्राम	56.00
9.	दावणगेरे	55.25
10.	तिरुचिरापल्ली	55.24

क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेन्नई, आर्थिक अवसरों में दिल्ली अव्वल

क्वालिटी ऑफ लाइफ

1.	चेन्नई	60.84
2.	कोयम्बटूर	60.33
3.	नवी मुंबई	59.93
4.	इंदौर	59.86
5.	वडोदरा	58.10

• चेन्नई इस सेग्मेंट में बेशक टॉप पर रहा, पर हेल्थ में उसे चौथी, एजुकेशन में 23वीं रैंक मिली।

क्वालिटी ऑफ एजुकेशन

1.	चंडीगढ़	83.27
2.	इंदौर	81.35
3.	बेंगलुरू	80.66
4.	अमृतसर	80.53
5.	जयपुर	79.80

• चौंकाने वाली बात यह है कि कोचिंग सिटी कहलाने वाले कोटा को 49वीं रैंक मिली है।

क्वालिटी ऑफ हेल्थ

1.	औरंगाबाद	61.69
2.	पिंपरी चिंचवाड़	58.93
3.	सोलापुर	58.59
4.	चेन्नई	58.24
5.	अमृतसर	56.88

• फरीदाबाद, भोपाल, कोटा, धनबाद, लखनऊ और आगरा सबसे निचले पायदान पर रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था

1.	कोयम्बटूर	98.06
2.	मदुरई	97.41
3.	वडोदरा	97.31
4.	चेन्नई	97.07
5.	हुबली धारवाड़	96.92

• श्रीनगर, धनबाद, पटना, बरेली, मेरठ, गुवाहाटी, रांची सबसे निचले पायदान पर रहे।

मनोरंजन

1.	कोयम्बटूर	56.10
2.	नवी मुंबई	47.75
3.	पुणे	34.41
4.	भोपाल	30.50
5.	लखनऊ	30.00

• बरेली, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली को सबसे निचली रैंकिंग दी गई है।

आर्थिक अवसर

1.	दिल्ली	100
2.	बेंगलुरू	58.15
3.	हैदराबाद	48.06
4.	चेन्नई	45.11
5.	पटना	40.22

• जयपुर, भोपाल, पुणे, ग्रेटर मुंबई, अहमदाबाद भी अवसरों वाले टॉप-10 शहर में शामिल हैं।

10 लाख की आबादी वाले 49 शहरों में ग्वालियर 31वें स्थान पर

ग्वालियर| केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग और म्युनिसिपल परफार्मेंस इंडेक्स-2020 की रैंकिंग में ग्वालियर प्रदेश के शहरों से पीछे रह गया है। देश के 111 शहरों में फरवरी में किए गए सर्वेक्षण में 10 लाख की आबादी के 49 शहरों में ग्वालियर को ओवरऑल 31वां स्थान मिला है।

भास्कर

कोरोना इफेक्ट : 10वीं-12वीं की परीक्षा ऑफलाइन, इस सत्र में नहीं खुलेंगे 5वीं तक के स्कूल

परीक्षाओं व शिक्षण सत्र पर स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा...

पॉलिटिकल रिपोर्टर. भोपाल | मप्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। इसी तरह 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं सरकारी स्कूलों में तो ऑफलाइन होंगी, लेकिन निजी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्वतंत्रता दे दी गई है। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि यदि निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है और वे इसी पैटर्न पर ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं तो लें, जो ऑफलाइन रहना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 5वीं तक के स्कूल चालू सत्र यानी मई तक बंद रहेंगे। अगले सत्र से प्रारंभ करने के बारे में निर्णय जल्द होगा।

अगला शैक्षणिक सत्र देर से शुरू होगा

परमार ने यह भी साफ कर दिया कि चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल और एक मई से हैं, इसलिए अगला शैक्षणिक सत्र भी देरी से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि पूरेमई परीक्षाएं चलेंगी। कोशिश यह होगी कि देरी की वजह से छात्र-छात्राओं को कोई दिक्कत न हो। जहां तक 6वीं से 8वीं की नियमित कक्षाओं को शुरू करने का सवाल है तो इस पर सैद्धांतिक समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। चालू सत्र में पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी।

6 करोड़ कर्मचारियों को राहत : पीएफ की ब्याज दरें नहीं घटीं, 8.5% ब्याज मिलेगा

मुंबई | पीएफ के दायरे में आने वाले 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। यानी साल 2019-20 की तरह 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। पहले आशंका जताई जा रही थी कि पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी जाएंगी, लेकिन गुरुवार को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग में ब्याज करों को बरकरार रखना का फैसला लियाग या। पिछले साल मार्च में पीएफ पर ब्याज कर सात साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। साल 2018-19 में यह 8.65% थी।

भास्कर

भास्कर खास • ब्रिटेन में मनगढ़ंत बीमारियां बताने का ट्रेंड बढ़ा, रॉयल कॉलेज को दिशा-निर्देश जारी करना पड़ा

'डॉ. गूगल' पर लक्षण पढ़ बच्चों को बीमार बता रहे पैरेंट्स, डॉक्टर को भरोसे में ले लेते हैं; विशेषज्ञों ने चेताया- यह बच्चों पर अत्याचार

एजेंसी | लंदन

ब्रिटेन में बच्चों के डॉक्टर खासे परेशान हैं। पैरेंट्स बच्चों में तरह-तरह की बीमारियों के लक्षण बताकर उनके पास ला रहे हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, तो कोई बीमारी नहीं निकलती। पैरेंट्स डॉक्टरों को बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को बीमारी है। कई बार वे समझाने में सफल भी हो जाते हैं। ऐसे वाकिए बार-बार हो रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ (आरसीपीसीएच) को डॉक्टरों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना पड़ा है।

दरअसल, बच्चों की सेहत में थोड़ा भी बदलाव होने पर पैरेंट्स 'डॉ. गूगल' यानी गूगल पर लक्षण सर्च करने लगते हैं। लक्षणों में मिलान होते ही वे मनगढ़ंत बीमारी तय कर लेते हैं और गलतफहमी पाल लेते हैं। आरसीपीसीएच ने इसे जोखिमभरा बताते हुए डॉक्टरों को कहा है कि वे मनगढ़ंत या अनुमान के आधार पर बताई बीमारी की जगह असल लक्षणों का ही इलाज करें। बच्चों को तात्कालिक रूप से कोई जोखिम न हो तो बच्चों से बात करें। पैरेंट्स से भी अलग से बात करें। पिछले दो साल में यह प्रवृत्ति बढ़ी है। यूके में 4000 कंसल्टेंट पीडिट्रिशन है और पिछले 2 साल में हर डॉक्टर के पास ऐसे केस पहुंचे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पैरेंट्स की यह चिंता वाजिब है, लेकिन ऐसे केस में बढ़ोतरी ऑनलाइन मिलने वाली गलत जानकारी के चलते हो रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन विशेषज्ञ डॉ. दान्या ग्लैसर के मुताबिक, यदि पैरेंट्स अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं, तो आपको वास्तव में बच्चों पर ध्यान देना होगा और यह पता लगाना होगा कि उनकी चिंता बेवजह न हो। आरसीपीसीएच में असिस्टेंट ऑफिसर और कंसल्टेंट पीडिट्रिशन डॉ. एमिलिया वावरजविक कहती हैं, 'यूके में 216 पीडिट्रिशन पर किए गए सर्वे में 92% ने कहा कि वे ऐसे केस का सामना कर रहे हैं।' कंसल्टेंट पीडिट्रिशन डॉ. एलिसन स्टौली कहती हैं, 'सोशल मीडिया पर गैर प्रमाणित स्रोत से लिए आर्टिकल के कारण ऐसी स्थिति बन रही है।

बच्चों के सिर तक मुंडवा रहे पैरेंट्स, बच्चे भी मानने लगते हैं कि वे बीमार हैं

स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि कई पैरेंट्स बच्चों के स्कूल छुड़वा रहे हैं। गैर जरूरी टेस्ट करवा लेते हैं। बच्चों के सिर मुंडवा रहे हैं, ताकि लगे कि कीमोथेरेपी चल रही है। एक डॉक्टर मना कर देता है तो वे दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्चों को अलग-थलग कर देते हैं। ऐसे में बच्चे मानने लगते हैं कि वे बीमार हैं।

पैरेंटिंग | कोरोना महामारी की पाबंदियों से बच्चों में बढ़ रहा मोटापे का खतरा

बच्चों में मोटापा : रोज़ाना 60 मिनट खेल, 9 घंटे की नींद जरूरी, खाते वक्त टीवी देखने से रोकें

डॉ. गार्गी पटेल
प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स
बीजेएमसी, अहमदाबाद
नेशनल वाइस प्रेसिडेंट,
आईएमए

कोरोना महामारी में लगाई गई विभिन्न पाबंदियों के कारण कई परिवार बच्चों के बढ़ते वजन को लेकर चिंतित हैं, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों से डाइटिंग कराई जाए। ऐसा करने से बड़े होने पर उनमें ईटिंग डिसऑर्डर का खतरा बढ़ता है। बच्चों के शरीर में बदलाव होना सामान्य प्रक्रिया है। फिर चाहे महामारी हो या फिर न हो। जब तक उनमें हाइट नहीं बढ़ती शरीर गोल-मटोल होता है। बच्चों के बढ़ते वजन की चिंता करने के बजाय माता-पिता को चाहिए के वे उनकी भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से देखभाल पर फोकस करें। ऐसा पाया गया है कि जब हम बच्चे को किसी चीज को खाने से रोकते हैं तो वह उसे और अधिक खाने लगता है। बच्चों को ज्यादा टोकने से बेहतर है कि खाने-पीने और रोजमर्रा की दूसरी आदतों जैसे खेल-कूद, डिजिटल एक्सपोजर के बेहतर शेड्यूल को फॉलो किया जाए।

इन 4 आदतों में बदलाव कर नियंत्रित कर सकते हैं वजन

1. तीन से पांच वर्ष के बच्चों को दिनभर एक्टिव रखें

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंसन (सीडीसी) के अनुसार 3 से 5 साल तक के बच्चों को दिन भर एक्टिव रहना चाहिए, जबकि 6 से 17 वर्ष तक के बच्चों को हर दिन 60 मिनट शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। एरोबिकट एक्टिविटी के अलावा हड्डियों को मजबूत करने वाली दौड़, कूद और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां जरूर शामिल हों।

2. 100 कैलोरी से कम वाले ये विकल्प वजन घटाने में सहायक

6 से 12 साल के बच्चों को रोज 1600 से 2200 कैलोरी की जरूरत होती है। कोरोना महामारी के दौर में घर में रहकर बार-बार खाने से बच्चों का कैलोरी इंटेक बढ़ गया है। ऐसे में जब वे कुछ खाने के लिए मांगे तो उन्हें एक गाजर, सेब या केला, थोड़े अंगूर दे सकते हैं। इनमें 100 से भी कम कैलोरी होती है।

3. टीवी देखते समय बच्चे जरूरत से अधिक खाते हैं, यह आदत बदलें

हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार दो घंटे से अधिक स्क्रीन के सामने बिताना नुकसानदायक है, लेकिन कोरोना के दौरान बच्चों का स्क्रीन टाइम ऑनलाइन क्लासेज की वजह से बढ़ गया है। एक शोध के अनुसार टीवी देखते समय बच्चे जरूरत से अधिक खाते हैं। इससे मोटापा बढ़ता है। इस खतरे से बचने के दो उपाय हैं। भोजन के समय बच्चों को टीवी न देखने दें और सोने के दो घंटे पहले स्क्रीन संबंधी गतिविधियां बंद करा दें।

4. 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटे तक सोना जरूरी

सीडीसी के अनुसार 3 से 5 साल के बच्चों को 10-13 घंटे (झपकी भी शामिल है), 6-12 साल, 9-12 घंटे और 13-18 वर्ष के किशोरों को 24 घंटे में 8-10 घंटे की नींद जरूरी है। दरअसल अपर्याप्त नींद अधिक खाने और शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है।

भास्कर

एक साल में 9 पायदान खिसके • शहर की 10 फीसदी आबादी से लिया गया था फीडबैक, इसके आधार पर ही रैंकिंग दी गई

बिजनेस और नौकरियां घटने से लिविंग इंडेक्स में पिछड़ा भोपाल

इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टर | भोपाल

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भोपाल एक साल में 9 पायदान नीचे खिसक गया। पिछले साल इस इंडेक्स में भोपाल 10वें नंबर पर था। शहर में रोजगार और व्यवसाय के अवसर कम होने और कुल मिलाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ में सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता नहीं होने के कारण भोपाल की रैंकिंग पीछे हुई है। इस बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सिटीजन परसेप्शन को जोड़ा गया था और शहर की 10 फीसदी आबादी से फीडबैक लिया गया था। इसके आधार पर ही रैंकिंग दी गई है। इसी तरह नगर निगम के कामकाज पर पहली बार जारी किए गए म्युनिसिपल परफारमेंस इंडेक्स में इंदौर पहले और तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक-एक पैरामीटर का एनालिसिस करें तो पता लगता है कि निगम भोपाल के कामकाज में बहुत सुधार की जरूरत है।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स... हर पैरामीटर पर नगर निगम भोपाल को कामकाज में बहुत सुधार की जरूरत

- **क्वालिटी ऑफ लाइफ...** शहर में एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सफाई और कचरा प्रबंधन, सड़क व परिवहन, सुरक्षा और मनोरंजन के संसाधनों की स्थिति।
- **इकॉनामिक एबिलिटी...** आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास की संभावनाएं।
- **सस्टेनेबिलिटी...** पर्यावरण, ग्रीन बिल्डिंग, बिजली व अन्य ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत।
- **सिटीजन परसेप्शन...** शहर के बारे में आम लोगों की राय।

	भोपाल		इंदौर		बेंगलुरू	
	अंक	रैंकिंग	अंक	रैंकिंग	अंक	रैंकिंग
• ओवरऑल	56.26	19	58.58	09	66.70	01
• क्वालिटी ऑफ लाइफ	57.92	08	59.86	04	55.67	12
• इकॉनामिक एबिलिटी	14.01	23	15.09	21	78.82	01
• सस्टेनेबिलिटी	51.68	39	61.62	10	59.97	13
• सिटीजन परसेप्शन	78.50	15	76.80	25	78	18

म्युनिसिपल परफॉरमेंस इंदौर vs भोपाल

इंदौर	अंक	रैंकिंग	भोपाल अंक	रैंकिंग
• ओवरऑल	66.08	01	• 59.04	03
• सर्विसेस	68.60	02	• 61.50	11
• फाइनेंस	69.69	01	• 62.45	07
• टेक्नोलाजी	54.57	01	• 39.12	08
• प्लानिंग	68.58	04	• 67.90	05
• गवर्नेंस	65.46	02	• 60.24	05

सिटीजन परसेप्शन में भोपाल देश भर में 15 वें नंबर पर है, जबकि इंदौर 25 वें नंबर पर है।

इकॉनामिक एबिलिटी में 23 वें नंबर पर

इंडेक्स के एक पैरामीटर इकॉनामिक एक्टिविटी में भोपाल 23 वें नंबर है। इंदौर 21 वें नंबर पर और बेंगलुरू पहले नंबर पर है। भोपाल में रोजगार के साधन अन्य शहरों की तुलना में कम होने से यह स्थिति है। इसी तरह क्वालिटी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी में भोपाल 39 वें, इंदौर 10 वें और बेंगलुरू 13 वें नंबर पर है।

म्युनिसिपल इंडेक्स में हम देश में तीसरे नंबर पर हैं। यह सही है कि इंदौर से हम पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन भोपाल प्रदेश की राजधानी का नगर निगम है, हमारे चैलेंजेस अलग हैं। जहां तक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात है तो उसमें निगम की सेवाओं के अलावा अन्य बातों का भी असर पड़ता है। **-वीएस चौधरी कोलसानी,** कमिश्नर, नगर निगम

खुलासा • कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी

व्यापमं परीक्षा में 10 टॉपर्स के एक जैसे नंबर और एक ही तरह की गलती, खुलासा हुआ तो अब जांच के आदेश

10 और 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा, 17 को लिस्ट जारी हुई

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराई गई कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस परीक्षा के सभी 10 टॉपर्स के एक जैसे नंबर आए हैं और गलती भी एक ही तरह की है। यह भी पता चला कि इनका कॉलेज भी एक ही है।

पीईबी ने यह परीक्षा फरवरी 11-12 फरवरी को आयोजित की गई थी। जब रिजल्ट आया तो ग्वालियर के राजकीय कृषि कॉलेज से बीएससी पास आउट 10 छात्रों के एक जैसे नंबर आ गए। आश्चर्य यह है कि कृषि विकास अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए हैं, वे भी एक जैसे हैं। उन्हें जितने मार्क्स मिले हैं, वह इस परीक्षा के लिए एक रिकॉर्ड है। यह सभी 10 चंबल क्षेत्र के हैं और इनमें से 9 एक ही जाति के बताए जाते हैं।

मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं

शिकायतकर्ता रमेश सिंह तोमर ने सवाल उठाया कि इन कैंडिडेट्स को सामान्य ज्ञान की परीक्षा में फुल मार्क्स मिले, लेकिन जब पीईबी ने आंसर शीट जारी की तो तीन सवालों के गलत जवाब दिए। दिलचस्प यह है कि टॉप स्कोरर परीक्षार्थियों ने भी उन्हीं तीनों सवालों के गलत जवाब दिए हैं। हम नहीं जानते कि यह संयोग है या साजिश, लेकिन यह कैसे संभव है कि उन्होंने समान गलत उत्तर दिए खासकर बेसिक सवाल का जो कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं।

8 साल में डिग्री पूरी की, फिर भी मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले

पीईबी ने 10-11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। इसमें जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। जानकारी के मुताबिक टॉपर्स में शामिल मनीष शर्मा के 194, जितेंद्र शर्मा के 189, निवेश शर्मा के 188 नंबर आए हैं। टॉपर्स में शामिल एक उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले हैं जबकि बीएससी में वह सांख्यिकी में 4 बार फेल हुआ था और 8 साल में उसकी डिग्री पूरी हुई थी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि व्यापमं ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी एनएसईआईटी को दी थी, जो पहले से आरोपों में रही है। वर्ष 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते एनएसईआईटी को ब्लैकलिस्ट किया गया था।

छात्रों ने की शिकायत

आखिर, उन्हें 200 में से 195 और 194 अंक मिले हैं

भास्कर संवाददाता ने ग्वालियर के उसी कॉलेज के एक पूर्व विद्यार्थी से बात की, जिन्होंने इनसे बात की थी। जयदीप भदौरिया नामक इस छात्र ने बताया कि सर्वोच्च 10 स्थानों पर रहे स्टूडेंट चंबल डिवीजन से हैं। इन्होंने बीएससी (कृषि विज्ञान) राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से की है। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने चार साल की डिग्री को पांच या अधिक सालों में पूरा किया। उन्होंने बताया कि यह लोग अपने कॉलेज में कहते थे कि अब अपना सलेक्शन तो पक्का है। ऐसे में क ही संभावना है कि या तो उनके पास प्रश्नपत्र था या फिर अंदर से उन्हें मदद मिली है। जयदीप ने कहा, पास होने वाले छात्रों को 200 में से 195 और 194 अंक मिले हैं, जो कि परीक्षा के इतिहास में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा इस मामले की जांच से पहले परीक्षा निरस्त होना चाहिए।

जैन कॉलेज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर : प्राचार्य

विदिशा ■ राज न्यूज नेटवर्क

एसएसएल जैन पीजी महाविद्यालय की प्राचार्य शोभा जैन ने चर्चा के दौरान बताया कि विगत दिवसों में सोषल मीडिया में भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, उसके सबंध में सत्यता है कि कॉलेज बंद होने की कगार पर नहीं है, परंतु निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मेरे कार्यकाल में यह संख्या निरंतर बढ़ते हुए आज ढाई से तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत है। कुछ नए कोर्स एमएसडबल्यू, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस, बीए, कप्यूटर साइंस एवं समाज शास्त्र विषय भी आए है। प्राचार्य शोभा जैन ने बताया कि जैन कॉलेज विदिशा का एक मात्र शोध संस्थान है जहां विद्यार्थी पीएचडी विभिन्न विषयों में कर चुके है एवं कर रहे है। जैन कॉलेज के प्राफेसर विभिन्न बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्य रह चुके हैं। प्राचार्य शोभा जैन के मार्गदर्षन में 8 विद्यार्थी पीएचडी डिग्री, डॉ एसके उपाध्याय के मार्गदर्शन में 13 विद्यार्थी, डॉ महेष थारानी के मार्गदर्शन में 6 विद्यार्थी को एवं डॉ एके रोंघे के मार्गदर्शन में 7 विद्यार्थी को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो चुकी है एवं कई विद्यार्थी रजिस्टर्ड है। महाविद्यालय में पहले अनुदान प्राप्त 65 प्राध्यापक कार्यरत थे अब केवल 8 प्राध्यापक ही कार्यरत है। यहीं हॉल में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का है जो लगभग 15 ही कार्यरत है। महाविद्यालय को शासकीय अनुदान केवल उपयुर्क्त कर्मचारियों के वेतन का ही आता है। बाकी कॉलेज में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक व्यय महाविद्यालय प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है। प्राचार्य शोभा जैन ने बताया कि महाविद्यालय में विवि स्तर की समस्यायें बहुत आती है जिनका समाधान हम पूरे स्टाफ के साथ कराने का प्रयत्न करते है इसलिए विवि संबंधित समस्यायें के लिए प्राचार्य एवं स्टाफ को दोषी ठहराना उचित नहीं है। जहां तक ऑन लाईन क्लासेस का आरोप लग रहा है, कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन के चलते ऑनलाइन क्लासेस संपन्न हुई। शासन के नियमों से बंधे हुए हैं। कह रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ाना था तो एडमिशन क्यों दिया। प्राचार्य को घड़ी उस समय भेंट की गई जब वह मेडीकल अवकाश पर थी। प्राचार्य एवं सारा स्टाफसमय पर आता है। प्राचार्य को कॉलेज की कक्षाओं का निरीक्षण करना, निर्माण कार्य देखना आदि बहुत से कार्य होते हैं इसलिए पूरे समय कुर्सी पर बैठना संभव नहीं है। महाविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है उसकी होटल से तुलना करना निदंनीय है। प्राचार्य शोभा जैन ने कहा कि जो भी छात्र प्रतिनिधि आते हैं उनसे बात करती हूं और ज्ञापन लेने से भी कभी मना नहीं किया। पूर्व में छात्रों द्वारा जो चक्काजाम हुआ था, विवेकानंद का पोस्टर धूप व पानी के कारण आधा फट गया था, जो कुछ छात्रों ने फड़कर नीचे गिरा दिया था, और वीडियो वायरल कर दिया, तहसीलदार ने छात्रों को समझाइश दी एवं नया चित्र बनाने के लिए निर्देशित किया। प्राचार्य ने तत्काल नया फोटो बनवाया। प्राचार्य ने बताया कि एडमीशन इतने अधिक होते हैं कि विवि एवं उच्च षिक्षा को आवेदन देना पड़ता है, पीजी कक्षा में सीट वृद्धि के लिए। धूम्रपान करने वाला वीडियो प्राध्यापक नहीं है। दो शासकीय कॉलेज के होने के बावजूद 17 कॉलेजों का परीक्षा केन्द्र था, अब दस कॉलेजों का बार बार विश्वविद्यालय से कहने के बाद ये संभव हुआ। स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा सेंटर भी सिर्फ जैन कॉलेज है।

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी

बच्चे अपने मन का डर निकालकर अभिभावकों से खुलकर करें चर्चा

बुरहानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय कन्या शाला खकनार में शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में पॉस्को एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुये सचिव, अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि पॉक्सो शब्द का हिन्दी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 है। जिसका संक्षिप्त नाम पॉस्को एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न, तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत नाबालिक बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। आये दिन समाज में बच्चों के साथ यौन अपराधों की खबरें मिलती रहती है, जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करती है।

इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को कठोर दंड की सजा के प्रावधान किये गये है। यह कानून बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। समाज में इस प्रकार की जानकारी मिलने पर शासन के सहयोग से कार्यवाही कर पीड़िता को न्याय प्राप्त हो सकता है। शासन की योजना के अनुसार पात्र पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग किया जाता है।

नरेन्द्र पटेल सचिव ने बच्चों से मैत्रीपूर्ण संबंध एवं घरेलू हिंसा पर चर्चा करते हुये बताया कि समाज में बच्चों के साथ आये दिन घटनाएँ होती रहती है। बच्चे अपने अभिभावक से डर या दबाव के कारण अपने मन की बात नहीं बता पाते है।

व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके व्यक्तित्व, दैनिक दिनचर्या के संबंध में मैत्रीपूर्ण तरीके से जानने की कोशिश करें जिससे बच्चे अपने मन की बात खुलकर परिवार के सामने रख सके। बच्चों को बाल अधिकार, उनके बुनियादी मानव अधिकार देता है। उक्त शिविर में पैरालीगल वालेटियर्स महेन्द्र जैन, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

वैचारिक गुलामी की तरफ ले जाएगी मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति

मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर जिले में सवाल उठते नजर आए। गुरूवार को डाइट में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर छात्र-छात्राओं ने बेबाकी से वाद-विवाद किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने पक्ष-विपक्ष में अपने विचार रखे। परिश्रम संस्था द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की विजेता अंशिका नेमा ने नई शिक्षा नीति को कागज का शेर बताते हुए कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में खोलना उपनिवेशवाद की ओर ले जाएगा और वैचारिक गुलामी आयेगी। वहीं उप विजेता रही कविता श्रीवास्तव ने शिक्षा नीति के पक्ष में अपने विचार रखे।

नरसिंहपुर ■ राज न्यूज नेटवर्क

चंद रोज पहले युवा संसद जैसा सफल बौद्धिक कार्यक्रम करने के बाद सामाजिक संस्था परिश्रम ने जिले के छात्र-छात्राओं को केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखने का मंच दिया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी खुलकर पक्ष-विपक्ष में वाद-विवाद किया। डाइट संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता विनायक परिहार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब सारी दुनिया शिक्षा व्यवस्था बनाने की शुरूआत कर रही थी उस दौर में हमारे देश में नालंदा जैसे हजारों उच्च शिक्षा केन्द्र हुआ करते थे। रोजगार परक शिक्षा प्रणाली का विकास करना आज की महती आवश्यकता है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति की समीक्षा विषय पर आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में 25 में से 15 प्रतिभागियों ने विपक्ष तथा 10 प्रतिभागियों ने पक्ष में अपने विचार रखे।

तथ्यों के साथ गिनाईं कमियां और खूबियां

आयोजन के दौरान छात्र-छात्राओं ने तथ्यों के साथ नई शिक्षा नीति की कमियां और खूबियां गिनाई। विजेता अंशिका नेमा ने नई शिक्षा नीति के विपक्ष में बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि जब पिछली शिक्षा नीति जीडीपी का 60 प्रतिशत नही बन पाई तो नई शिक्षा नीति कैसे 6 प्रतिशत तक बन पायेगी। उपविजेता कविता श्रीवास्तव ने पक्ष में बोलते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा समेत संस्कृत और मातृभाषा की अनिवार्यता और अनुभव, अनुसंधान समेत शोध परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कविता ने कहा कि स्नातक करते वक्त बीच में पढ़ाई छोड़ देने पर साल बर्बाद नही होगा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम बाद में पुनः पढ़ाई शुरू करने पर विद्यार्थियों की मदद करेंगे।

किसी ने कहा सही किसी ने कहा गलत

विपक्ष में बोलने वाले वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को बीमार आदमी को अच्छे कपड़े पहना देने वाली बताते हुए इसे निजीकरण को बढ़ावा देने वाली भी बताया। वहीं पक्ष में बोलने वाले विद्यार्थियों ने इसे रोजगार देने वाली और छात्र हितैषी नीति बताया। शिक्षा नीति के पक्ष में शिवानी नेमा, आरती कुशवाहा, वैशाली पांडे, कविता श्रीवास्तव, वैभव पाटकार, पार्वती चौधरी, सिद्धि नेमा, उमेश प्रजापति, स्वाति मिश्रा, रीता नेमा आदि ने विचार रखे। वहीं विपक्ष में रंजनी कुशवाहा, चंद्रप्रभा नौरिया, दीपिका साहू, प्रियंवदा तिवारी, शिवम राजपूत, अंशिका नेमा, रिया मंसूरी, मानसी जैन, दीक्षा लोधी, जीनत मंसूरी, रश्मि चौधरी, अंजलि साहू, एकता प्रजापति आदि ने अपने विचार रखें। कार्यक्रम के संयोजक एवं परिश्रम संस्था के अध्यक्ष महेन्द्र कौरव ने विषय की प्रस्तावना रखते हुए आयोजन को व्यक्तित्व विकास के साथ ही अभिव्यक्ति का अवसर बताया। प्रतियोगिता के निर्णायक विवेक सिंह एवं बसंत श्रीवास्तव थे।

एसडीएम ने किया कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल का निरीक्षण

खिरकिया (आरएनएन)। जीवन में सफलता पाने के लिए एकाग्रता जरूरी है। इसलिए अभी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे तथा अपने लक्ष्य भी अभी से निर्धारित कर ले ताकि भविष्य में अपने गोल को सरलता से प्राप्त किया जा सके। यह बात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रीता डेहरिया द्वारा स्थानीय कन्या हायर सेकेड्री स्कूल की छात्राओं से चर्चा के दौरान की। श्रीमती डहेरिया स्थानीय निर्वाचन के लिए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल

चयन हेतु अकास्मिक रूप से पहुँची थी। बालिकाऐं अचानक अपने बीच पाकर प्रफुल्लित हो गई। श्रीमती डहेरिया ने कन्या हायर सेकेड्री के अति उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षों का भी निरीक्षण किया तथा स्कूल प्राचार्य मनोज झिंगन, नगर पालिका सीएमओ तथा लोक निर्माण विभाग को चयनित कमरों की साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था एवं टूट-फूट मरम्मत के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक प्रौढ शिक्षा अधिकारी उमाकांत वर्मा, सीएमओ आत्माराम सांवरे, निर्वाचन प्रशिक्षक प्रदीप कुमार रिछारिया, पटवारी अविनाश भारद्धाज, बीएसी सुनील कुमार सोंधिया भी उपस्थित थे ।

युवक कांग्रेस ने बाल आयोग से की शिकायत

स्कूलों में लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप

चैलेंज, भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूल खुलने के बाद फीस वसूले जाने की शिकायतें आ रही हैं। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए युवक कांग्रेस मैदान में उतर आया है। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली पर अंकुश लगनी चाहिए। अभिभावकों से लेट फीस के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। इधर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलते ही संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। युवक कांग्रेस मध्यप्रदेश मीडिया के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि फीस वसूली समेत अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से शिकायत दर्ज कराई। उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इसमें जबरन वसूली की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हमने उन्हें बताया कि प्रदेश के ऐसे स्कूलों पर नकेल कसना है। सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल लेट फीस के नाम पर मनमानी कर रहे हैं।

शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास होना चाहिएः मुख्यमंत्री

शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

शिक्षा का अर्थ तोते की तरह रटना, बस्ते के बोझ से दबे रहना और परीक्षा देना नहीं है। शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास तथा उनकी प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में 21वीं सदी में शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कही। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद् राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए हैं।

शिक्षा पथ प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष रविंद्र कान्हरे, आयोजन समिति के संयोजक डॉ शशि रंजन अकेला आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा पथ प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन भी किया।

मप्र पहला राज्य, जहां नई शिक्षा नीति को लागू करने गठित हुआ टास्क फोर्स

कार्यक्रम में शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि कोई संस्थान अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। शिक्षा में सुधार के लिए टास्क फोर्स बनेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षाविदों को जोड़ा जाए, जो नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को मध्यप्रदेश में किस तरह व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, इस संबंध में सुझाव दें।

इन विषयों पर होगा मंथन

इस दो दिवसीय संगोष्ठी में नई दिल्ली, हैदराबाद, मेरठ, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, बिहार और बिलासपुर समेत अन्य जगहों से कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविद् शामिल होंगे। ये सभी विषय विशेषज्ञ अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षक और शिक्षा के प्रावधान, नेतृत्व, शासन और शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का विनियमन, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता और मानक विषय, छात्रों के अधिकार एवं विशेष शिक्षा, अंग्रेजी भाषा अध्ययन,शिक्षा में प्रयोग, शिक्षक-शिक्षण संस्थाओं की बहुसंकायी प्रकृति जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सिफारिशों को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

मंथन से उपजे विचार मील का पत्थर साबित होंगे

श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सतत प्रयास कर रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित गुणवत्तापूर्ण और ज्ञान आधारित होना चाहिए। इस मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा।

आत्म-निर्भर मप्र में शिक्षा का अहम स्थान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाए गए रोड मैप में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। अच्छी तकनीकी शिक्षा के लिए ग्लोबल स्किल पार्क तथा आदर्श आईटीआई बनाए जा रहे हैं।

शिक्षकों की ट्रेनिंग में बदलाव कर नई शिक्षा नीति को बनाया जाएगा बेहतर

21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी के पहले शिक्षाविदों ने रखे तर्क

देशभर से 250 से अधिक शिक्षाविद कर रहे हैं सहभागिता, 6 मार्च को होगा संगोष्ठी का समापन

हरिभूमि न्यूज >> भोपाल

शिक्षक बाय चांस नहीं, बाय च्वॉइस बनना चाहिए। ऐसा होने पर वे मन से पढ़ाएंगे और आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण करेंगे। आजादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई कमीशन बने, नीतियां बनी, परन्तु उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया।

इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए देश भर के शिक्षाविदों ने गंभीर चिंतन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यह बात शुक्रवार को 21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने कही। दो दिन तक चलने वाली इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 250 से अधिक शिक्षाविद सहभागिता कर रहे हैं। संगोष्ठी का समापन 6 मार्च को होगा।

शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने कहा

अच्छा बदलाव आएगा

इस कार्यक्रम के जरिए एक अच्छा बदलाव आएगा। मेरे हिसाब से एक टीचर अगर सच्चा शिक्षक बन जाए तो किसी भी अन्य प्रयास की जरूरत ही नहीं है। एक टीचर को पता होना चाहिए उसका दायित्व क्या है। शिक्षा नीति को यदि कोई बदल सकता है कोई बेहतर कर सकता है तो वो एक शिक्षक ही है।

हिमांशु दुबे
भूतपूर्व महानिदेशक एवं कुलपति
चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी, गुजरात

सबको भागीदारी देनी होगी

अभी तक जो शिक्षा नीति थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ था। नीति तो ठीक थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति और भी बेहतर है। शिक्षा का स्तर अब और भी बढ़ गया है ऐसे में सबको इसमें अपनी भागीदारी देनी होगी, जिससे शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में, इसका अच्छा असर पड़े।

रामकृष्ण राव
अखिल भारतीय अध्यक्ष
विद्या भारती

पूरा ध्यान शिक्षक शिक्षा पर

इस संगोष्ठी का मेन फोकस टीचर्स एजुकेशन पर है। शिक्षकों की ट्रेनिंग में कुछ बदलाव की जरूरत है। यदि हम शिक्षक की ट्रेनिंग नई शिक्षा नीति की तरह से नहीं करेंगे तो पॉलिसी बस पॉलिसी ही बन कर रह जाएगी। यह दो दिवसीय संगोष्ठी इन्हीं मुद्दों पर हो रही है कि पहले हमको शिक्षक को तैयार करना है तब हम आगे बढ़ पाएंगे।

डॉ. सुशील गुप्ता
कुलपति, आरजीपीवी

सीखने की चार स्थितियां पठन, मनन, चिंतन और संकेतन : प्रो. जगदीश कुमार

शुभारंभ समारोह में ऑनलाइन जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने आधुनिक विज्ञान के उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि लर्निंग बाय डूइंग सीखने का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन आज हमारी शिक्षा सिर्फ लेक्चर सुनने पर केंद्रित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सीखने की चार स्थितियां बताई हैं, पठन, मनन, चिंतन और संकेतन। आज आधुनिक विज्ञान इसी प्रक्रिया से सीखने को सबसे अधिक प्रभावी बताता है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई तरीकों के प्रयोग शामिल किए गए हैं।

मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्थक होगा : मंत्री परमार

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जो काम होना चाहिए थे, वे नहीं हो पाए। इस राष्ट्रीय मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा। संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सिफारिशों को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

सीबीएसई ने जारी की संशोधित समय सारिणी

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संशोधित विस्तृत समय सारिणी यानी डेटशीट जारी कर दी है। इस बार बोर्ड ने पहले से घोषित डेटशीट में बदलाव करते हुए नई डेटशीट जारी की है। इसके साथ ही सीबीएसई ने शुक्रवार को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए व्यावहारिक परीक्षाएं, परियोजनाएं, आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 04 मई, 2021 से शुरू होंगी, लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा 07 जून, 2021 और कक्षा 12वीं की परीक्षा 14 जून को समाप्त होगी।

10वीं-12वीं की परीक्षाओं के दौरान नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह स्थिति स्पष्ट की

प्रशासनिक संवाददाता ■ भोपाल

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ईव्हीएम की चैंकिंग और सेटअप के लिए इंजीनियर मिलने में देरी हो रही है।

(शेष पृष्ठ नौ पर...)

नहीं टलेंगे चुनाव

आयुक्त सिंह ने इस संभावना से इंकार किया है कि कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ने के कारण चुनाव कुछ समय के लिए टाले जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है। यानी वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी।

परमाणु बम से 65 हजार गुना ज्यादा खतरनाक

आज पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा एस्टेरॉयड एपोफिस

एजेंसी ● वॉशिंगटन

editor@peoplessamachar.co.in

अंतरिक्ष का तीसरा सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड एपोफिस 6 मार्च यानी शनिवार को धरती के करीब से गुजरेगा। कुछ दिन पहले ही इसकी पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। करीब 370 मीटर चौड़ी इस चट्टान के अगले 48 सालों में धरती से टकराने का खतरा है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी संभावना बहुत कम है। इसका वर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्ट पर 24 घंटे लाइव प्रसारण किया जाएगा।

टकराने पर होगा विनाश: 27 अरब किलो का यह एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराता है तो इससे एक मील चौड़ा व 518 मीटर गहरा गड्ढा बन सकता है। यही नहीं, इससे 88 करोड़ टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर असर होगा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 65 हजार गुना ज्यादा भयानक होगा।

लगातार बढ़ता जा रहा है आकार

एपोफिस एस्टेरॉयड निकेल और लोहे से बना है और रेडॉर इमेज से पता चलता है कि यह लगातार लंबा हो रहा है। इसका आकार अब मूंगफली की तरह होता जा रहा है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि इसके अभी और ज्यादा विश्लेषण की जरूरत है। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह धरती से वर्ष 2068 में टकराएगा या नहीं। इससे पहले के शोध में कहा जा रहा था कि इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना केवल 2.7 प्रतिशत ही है। तबाही का देवता एपोफिस फ्रांस के एफिल टावर से आकार में काफी बड़ा है।

वर्ष 2068 में धरती से टकराने की आशंका

आकलन के मुताबिक एस्टेरॉयड एपोफिस धरती से करीब 1 करोड़ 60 लाख लाख किमी की दूरी से गुजरेगा। इतनी दूरी से गुजरने के कारण एस्टेरॉयड का परिक्रमा पथ प्रभावित नहीं होगा। एस्टेरॉयड एपोफिस को टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकेगा। हवाई यूनिवर्सिटी के खगोलविद डेविड थोलेन ने कहा कि सुबारू टेलिस्कोप से मिले डाटा के आधार पर खुलासा हुआ है कि एपोफिस बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2029 में यह एस्टेरॉयड अगर केवल ठीक-ठीक दूरी से गुजरता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका रास्ता बदल देगी और यह वर्ष 2068 में वापस आएगा और 12 अप्रैल 2068 को पृथ्वी से टकरा सकता है।

छात्रा के सवाल का जवाब नहीं दे सके टिकैत, माइक छीना

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के मंच पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से एक बेटी ने डेढ़ मिनट में तीन-चार सवाल पूछ लिए, लेकिन टिकैत कोई जवाब नहीं दे सके और छात्रा के हाथ से माइक ले लिया गया। इसके बावजूद वह खामोश नहीं हुई। माइक ले लिए जाने के बाद भी बोलती रही। उसने कहा कि देश का युवा सवाल तो पूछेगा ही कि आखिर यह सब कहां पर जाकर थमेगा। हमें नहीं पता कि 26 जनवरी जैसी घटना में किसका हाथ था, लेकिन इसका हमारे समाज, मेल-मिलाप पर क्या असर पड़ रहा है, यह देखा जाना चाहिए।

राकेश टिकैत शनिवार को दिल्ली के ढांसा बार्डर पर चल रहे धरने को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान हरियाणा से आई एक छात्रा मंच पर पहुंची और कुछ बोलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद

ढांसा बार्डर पर हंगामा

- **बोली, हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, यह देखा जाना चाहिए**
- **देश का युवा सवाल तो पूछेगा ही, माइक हाथ से लेना उचित नहीं**

छात्रा को माइक दिया गया। कुछ समय तक प्रदर्शन के समर्थन में बोलने के बाद छात्रा ने राकेश टिकैत से सवाल पूछना शुरू किया। छात्रा के यह कहते कि लाल किला की घटना के पीछे आप हो या नहीं, मुझे नहीं पता.. प्रदर्शनकारियों ने उसका माइक बंद कर दिया। इसके बाद राकेश टिकैत सहित अन्य प्रदर्शनकारी बीच में बोलने लगे। टिकैत ने अपनी बात रखी, लेकिन छात्रा के सवालों का जवाब नहीं मिला। छात्रा जब टिकैत से सवाल पूछ रही थी तो उस दौरान भी बीच-बीच में कहा जा रहा था कि माइक ले लो।

मप्र हाई कोर्ट में नियुक्त होंगे तीन नए जज

इंदौर (टीम नईदुनिया)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तीन नए जज नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने इंदौर के अधिवक्ता विवेक शरण, ग्वालियर की अधिवक्ता निधि पाटनकर व जबलपुर के अधिवक्ता प्रणय वर्मा को हाई कोर्ट जज बनाए जाने की सिफारिश कर दी है। लिहाजा, अब इन तीनों के नामों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की मुहर लगना शेष है।

सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने दो मार्च को आयोजित मीटिंग में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित तीन नामों के अलावा पंजाब हरियाणा व जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भी एक-एक अधिवक्ता के नाम को स्वीकृत कर जज बनाए जाने की सिफारिश कर दी है।

सर्विस मेटर और शिक्षा से जुड़ी याचिकाओं में रही शरण की रुचि

हाई कोर्ट जस्टिस बनने जा रहे एडवोकेट विवेक शरण ने 90 के दशक की शुरुआत में अपनी वकालात शुरू की थी। वे सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर के जूनियर थे। उनके पिता जस्टिस मैथलीशरण इंदौर जिला जज रहे हैं। बाद में वे हाई कोर्ट जस्टिस भी बने। बहन विधि सक्सेना वर्तमान में जिला जज हैं। विवेक शरण असिस्टेंट सालिसिटर जनरल (केंद्र सरकार के वकील) और राज्य सरकार के वकील भी रहे हैं। सर्विस मामले और शिक्षा से जुड़ी याचिकाओं में उनकी खासी रुचि रही है। वे लंबे समय तक दैअविवि के वकील भी रहे। शरण ने अंतरराष्ट्रीय कानून में पीएचडी भी की है।

विवेक शरण

निधि का इंदौर में है मायका

ग्वालियर की अधिवक्ता निधि पाटनकर का इंदौर में मायका है। उनकी शादी ग्वालियर के अभिजीत 'रवि' पाटनकर से हुई। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अंजिक्य अमेरिका में और बेटी अनन्या ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रही है। निधि के पति रवि शहर की प्रतिष्ठित अभि स्मृति फैथॉलोजी संचालित करते हैं, वहीं मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की विभिन्न टीमों में चयनकर्ता की भूमिका भी निभा रहे हैं। रवि ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में दस साल तक लगातार सचिव पद भी संभाल चुके हैं।

निधि पाटनकर

होशंगाबाद का नाम 'नर्मदापुरम' करने का संकल्प पारित

विधानसभा : पश्चिम मध्य रेल के खन्ना बंजारी स्टेशन का नाम विजयनाथधाम करने पर भी सर्वसम्मति

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश विधानसभा में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह संकल्प भाजपा विधायक [illegible], [illegible] सिंह, ठाकुरदास नागवंशी, डा. सीतासरन शर्मा व प्रेमशंकर वर्मा ने रखा। इसका विपक्ष ने भी समर्थन किया। [illegible] नर्मदापुरम नामकरण करने के लिए संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

डा. शर्मा ने कहा 14वीं शताब्दी में हुशंगशाह गौरी यहां आया था। उसके नाम पर शहर का नामकरण किया गया। कुछ दिन बाद वह तो चला गया, लेकिन शहर अभी तक उसके नाम पर जाना जाता रहा। [illegible] नर्मदापुर का इतिहास मिलता है। [illegible] धार्मिक महत्व वाले इस शहर का नाम आक्रमणकारी के नाम पर होना गलत है। [illegible] सिंह ने कहा कि लुटेरे के नाम पर शहर का नाम क्यों रखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने के संकल्प का समर्थन किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस अशासकीय संकल्प को पारित करने की घोषणा की।

उधर, संजय पाठक के एक अन्य

अशासकीय संकल्प को [illegible] ने रखा। उन्होंने पश्चिम मध्य रेल के खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन का नाम विजयनाथधाम करने का संकल्प प्रस्तुत किया। विजयनाथधाम रेलवे स्टेशन के नजदीक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। [illegible] सर्वसम्मति से पारित किया गया।

यह है इतिहास

होशंगाबाद (नर्मदापुरम) नर्मदा नदी के किनारे बसा है। [illegible] के अनुसार, [illegible] गौरी सन 1406 में गद्दी पर बैठा था, [illegible] उसी के नाम पर यह शहर बसाया था। [illegible] होशंगाबाद नाम रखा गया था। नर्मदा पुराण में इस शहर का नाम नर्मदापुर [illegible] है। [illegible] से प्राप्त हुआ है कि परमार काल [illegible] इस शहर का नाम नर्मदापुर प्रचलन में था। शहर में कई प्राचीन धार्मिक मंदिर/स्थल हैं। [illegible] का नामकरण पहले से ही नर्मदापुरम किया जा चुका है।

अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए विधेयक लाएगी सरकार : भूपेंद्र सिंह

भोपाल (ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए सरकार बजट सत्र में ही विधेयक लाएगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम का मसौदा तैयार है। [illegible] फोकस किया जाएगा। [illegible] अनुमति [illegible] वैध करवाया जा सकेगा। यह जानकारी सदन में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को दी। [illegible] अवैध कालोनियों के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने को लेकर सवाल पूछा था। मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदेश में कुल [illegible] अवैध कालोनियां हैं। 2016 में [illegible] मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। कई कालोनियां वैध भी हुईं और फिर ग्वालियर हाई कोर्ट का [illegible] आ गया। [illegible] रुकी हुई थी। ऐसी कालोनियों के रहवासियों के हितों को देखते हुए तय किया है कि अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसकी कार्यवाही पूरी कर ली गई है और बजट सत्र में ही संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रावधान किया जा रहा

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह। ● नईदुनिया फाइल फोटो

है कि भवन बनाने के लिए जितनी अनुमति ली गई है, उससे अधिक [illegible] निर्माण को निश्चित शुल्क के साथ वैध करवाया जा सकेगा। 2016 के प्रावधान में यह सीमा अधिकतम दस प्रतिशत थी।

भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान की होगी जांच : [illegible] के सवाल पर मंत्री ने बताया भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान में [illegible] हुई है तो जांच कराई जाएगी। [illegible] 2011 के मास्टर प्लान में [illegible] 2021 में [illegible] और [illegible] अवैध कालोनियां कट गईं, लेकिन उन्हें एक बार फिर [illegible] प्रस्तावित कर दिया है।

विधानसभा में गूंजा सड़कों, पुलों के जर्जर होने का मुद्दा

भोपाल (ब्यूरो)। रीवा और राजगढ़ की खराब सड़कों का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में गूंजा। [illegible] प्रजापति और [illegible] सिंह ने यह मुद्दा उठाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा कि रीवा का [illegible] पुल जर्जर हो चुका है। [illegible] बायपास बनाया गया तो इस पुल को [illegible] के बजाय छोड़ दिया गया। इसी पुल से गिरने के कारण मेरे छोटे भाई की मृत्यु हुई थी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने आश्वासन दिया कि पुल और सड़कों की मरम्मत का काम जल्द ही कराया जाएगा। ध्यानाकर्षण के दौरान [illegible] सिंह ने कहा कि राजगढ़ से [illegible] को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर हालत में है। [illegible] पुल के डूब जाने के बाद राजगढ़, गुना के श्रद्धालुओं को [illegible] के दर्शन करने के लिए 40 - 50 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि सड़क खराब [illegible] है। जल संसाधन विभाग का पुल बनाना है। विभागीय अधिकारियों से चर्चा हुई है। सड़क के [illegible] चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाएगा। वहीं, [illegible] प्रजापति ने रीवा की सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि [illegible] से [illegible] होते हुए [illegible] मार्ग [illegible] है। [illegible] का पुल बहुत जर्जर है। [illegible] हो चुकी है। नये पुल [illegible] जरूरी है। [illegible] अन्य विधायकों ने भी सड़कें [illegible] होने की बात उठाई।

जनता की मदद के लिए परेशान होने वाले नेता थे नंदकुमार चौहान

लोकसभा सदस्य नंदकुमार सिंह चौहान जनता के लिए परेशान रहने वाले नेता थे। वे हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। [illegible] जीवन की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की और नगर पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद सदस्य तक रहे। संगठन की [illegible] मध्य प्रदेश में भाजपा को [illegible] में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। [illegible] से लोग [illegible] उनकी लोकप्रियता का अंदाज लगाया जा सकता है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विधानसभा में नंदकुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देते हुए कही। वहीं, कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि वे सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा [illegible] के [illegible] और बुरहानपुर के दौरे पर मुझे जाना था, लेकिन उनके असमय होने की [illegible] से निरस्त कर दिया।

एक लाख...छात्र-छात्राएं सीधे तौर पर होंगे प्रभावित

बीयू ने मार्कशीट दी नहीं, परीक्षा फॉर्म की तारीख घोषित कर दी

स्नातक स्तर की परीक्षाओं के लिए 20 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

बरकतउल्ला विवि द्वारा स्नातक स्तर की सभी वर्ष की परीक्षा कराने के लिए तारीख घोषित कर दी है। इनमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीबीएस, बीसीए और बीकॉम आनर्स शामिल हैं। इन परीक्षाओं के लिए नियमित, प्राइवेट और पूर्व छात्र 5 से 20 मार्च तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इन सभी विषयों में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के करीब एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। तीनों परीक्षाओं के लिए 1330 रुपए शुल्क तय किया गया है। वहीं पूर्व छात्रों के लिए 1580, विदेशी छात्रों के लिए 2720 और एक विषय के लिए 760 रुपए फीस तय की गई है। यदि कोई देरी से फॉर्म भरता है तो परीक्षा शुरू होने के सात दिन पहले तक एक हजार रुपए विलंब शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन असल समस्या विद्यार्थियों के सामने यह है कि वे एमपी ऑनलाइन पर फार्म नहीं भरे पाएंगे, क्योंकि जनरल प्रमोशन वाली मार्कशीट अब तक उन्हें नहीं मिली है। यहां तक कि ऑनलाइन भी मार्कशीट उपलब्ध नहीं है। इस मामले में विवि के कुलपति आरजे राव से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्दी ही सभी विद्यार्थियों को मार्कशीट दे दी जाएगी।

विवाहिता को श्रीमती लिखना अनिवार्य है

बीयू ने सर्कुलर में आदेश दिए हैं कि यदि कोई महिला विवाहित है तो उसे श्रीमती लिखना है। और यदि अविवाहित है तो पिता के नाम का उल्लेख करे। फोटो नई होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सर्कुलर में यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी कि ऑफलाइन। सूत्रों के मुताबिक परीक्षाएं अप्रैल की बजाय मई में होने की संभावना है। अभी फार्म भरे जाएंगे।

भ्रष्टाचार • रंगेहाथों पकड़े गए थे, इसीलिए आईएएस अवार्ड नहीं हुआ

दस हजार की घूस, शिवपुरी के पूर्व एडीएम शेख को पांच साल की कैद

बाबू को भी चार साल की सजा और जुर्माना, 5 साल पुराना है मामला

भास्कर न्यूज | शिवपुरी

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय की कोर्ट ने शुक्रवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत के मामले में शिवपुरी जिले में एडीएम रहे जेडयू शेख (वर्तमान में मंत्रालय में पदस्थ) को पांच साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। छह साल पहले लोकायुक्त पुलिस ने जेडयू शेख को घूस लेते हुए रंगे हाथ उनके ही चैंबर में पकड़ा था। रिश्वतकांड में नाम आ जाने की वजह से इन्हें आईएएस अवार्ड भी नहीं हो पाया था, जबकि इस कांड के अगले महीने ही होने वाली डीपीसी में इनका प्रस्तावित था। इसी रिश्वत मामले में कोर्ट ने बाबू (वर्तमान में रिटायर) रामगोपाल राठौर को भी चार साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शेख के पास खनिज अधिकारी का प्रभार था

मालूम हो कि तत्कालीन एडीएम शेख के पास उस समय खनिज अधिकारी का प्रभार था। एक खदान की लीज के बदले में ही उनके द्वारा ठेकेदार से रिश्वत मांगी गई थी।

खदान की लीज के एवज में 30 लाख रु. मांगे थे, 15 हजार रुपए की पहली किस्त मिलते ही दबोचा

तत्कालीन शिवपुरी एडीएम जेडयू शेख।

तत्कालीन खनिज विभाग के बाबू रामगोपाल राठौर।

रिश्वत की पहली किस्त के 15 हजार केमिकल युक्त नोट भेजे

फरियादी दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्टोरेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज सेक्शन के क्लर्क रामगोपाल राठौर ने 30 हजार रु. की रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया था कि एडीएम शेख को भी हिस्सा देना होगा। गोपाल ने दिवाकर की बात भी एडीएम शेख से करा दी थी। दिवाकर ने लोकायुक्त में मामले की शिकायत कर दी। शिकायत सच पाने पर लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त के 15 हजार रुपए केमिकल युक्त नोट दिवाकर के जरिए एडीएम शेख को भेजे। इसमें दस हजार रुपए एडीएम और 5 हजार रुपए बाबू का हिस्सा था। 7 नवंबर 2015 को एडीएम शेख ने जैसे ही रकम हाथ में ली तो इशारा पाकर लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद क्लर्क गोपाल को भी हिरासत में ले लिया था।

आईएएस अवार्ड के लिए नाम प्रस्तावित था

62 साल के एडीएम जेडयू शेख राज्य प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। 1998 में अपर कलेक्टर बने। रिश्वतकांड में नाम आने के अगले महीने जेडयू शेख का नाम आईएएस अवार्ड के लिए होने वाली डीपीसी के लिए प्रस्तावित था। मार्च 2018 में भी मप्र के 17 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में अफसर बन गए। लेकिन रिश्वतकांड की वजह से जेडयू शेख को आईएएस अवार्ड नहीं हो पाया।

आज का इतिहास

- 1508: बाबर के बेटे हुमायूं का अफगानिस्तान के काबुल में जन्म।
- 1712: न्यूयॉर्क शहर में दास विद्रोह शुरू हुआ।
- 1886: नर्सों की पहली पत्रिका नाइटिन्गेल प्रकाशित हुई।
- 1960: स्विट्जरलैंड ने निकाय चुनाव में महिलाओं को मतदान का हक मिला।
- 1961: भारत का पहला वितरीय डेली समाचार पत्र 'द इकोनोमिक टाइम्स' बॉम्बे में लॉन्च हुआ।
- 1962: महान क्रांतिकारी और योद्धा अंबिका चकव्रती का निधन।
- 1991: तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने पद से इस्तीफा दिया।
- 2009: भारतीय वायुसेना को 30 साल सेवाएँ देने के बाद स्किग-विंग लड़ाकू विमान मिग-23 ने अन्तिम उड़ान भरी।

आज का इतिहास

1892 अम्बिका चक्रवर्ती, प्रसिद्ध क्रान्तिकारी और नेता का निधन हुआ।

1995 मोटूरि सत्यनारायण - दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार आन्दोलन के संगठक का निधन हुआ।

2001 फिजी में महेन्द्र चौधरी के खिलाफ पार्टी में ही विद्रोह की स्थिति बनी।

2004 उत्तर कोरिया का यूरेनियम आधारित कार्यक्रम होने से फिर इन्कार।

2008 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की दया याचिका खारिज की।

2009 भारतीय वायुसेना को तीन दशक तक अपनी सेवाएँ देने के बाद स्किंग-विंग लड़ाकू विमान मिग-23 ने अन्तिम उड़ान भरी।